

हरियाणा विधान सभा

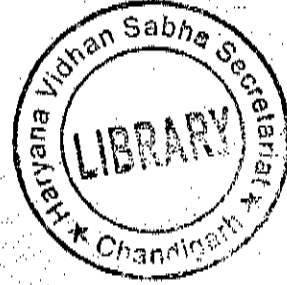
की

कार्यवाही

10 मार्च, 2010

खण्ड-1, अंक-4

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बुधवार, 10 मार्च, 2010

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4) 22
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(4) 32
विभिन्न विषयों का उठाया जाना / वाक-आउट्स	(4) 32
वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(4) 34

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 10 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (स० हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

तारकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बरज, अब सवाल होंगे।

Collection of Revenue from Mineral Quarries

* 156. **Shri Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the total revenue collected from minor mineral stone quarries during the financial year 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 year wise together with the number of such quarries in the State?

P.W.D. (B & R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the year wise revenue collected from minerals in the State and revenue collected from minor mineral "stone" quarries along with number of such stone quarries operated is as under—

Year	Total Revenue collected from Minerals	Revenue collected from stone quarries	Number of stone quarries operated
2005-06	153.34	114.49	294
2006-07	136.26	105.33	299
2007-08	215.70	156.99	176
2008-09	195.24	144.72	169
2009-10	226.00	160.62	196
* upto January, 2010			

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि इन्होंने खनिज भाफिया को खत्म किया है। यह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, जहाँ तक स्टोन क्वैरीज के नम्बरज हैं इसमें हमारी कलैक्शन और भी हो सकती थी। स्टोन क्वैरीज 294 से घटकर 196 ही रह गई हैं, यानि 100 क्वैरीज घट गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन क्वैरीज के घटने का क्या कारण है? दूसरे में यह भी जानना चाहूँगा कि आज स्टेट में स्टोन क्वैरीज की क्या पोजीशन है? तीसरे यह जानना चाहूँगा कि क्या 28 फरवरी, 2010 के बाद हरियाणा प्रदेश में सभी क्वैरीज चाहे वह माईनर माईन्ज की हैं या मेजर माईन्ज की हैं, वे बंद हो चुकी हैं?

श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 3 सवाल पूछे हैं। एक तो मई से दिसम्बर, 2002 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसके बाद सब-स्टोन क्वैरीज except for two mines, एक सिराही में और एक खौरी जमालपुर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में हैं जिनकी 5 फरवरी, 2009 तक नार्मल कोर्स ऑफ लीज है तब तक चलाने की इजाजत थी, बाकी की सब बंद कर दी गई थी। उसके बाद लास्ट आर्डर है जिसके बारे में जानने के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है। सर, ऐक्टिविटीज स्टोन और अदर मिनरल्स की सारी माइनिंग 28 फरवरी, 2010 से अपने प्रान्त के अन्दर बंद हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन बैंच ने राजस्थान स्टेट पर भी इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी है। तीसरे सर, इन्होंने पूछा है कि आगे हम क्या करने वाले हैं? उसके बारे में इनको बताना चाहूंगा कि सैन्ट्रली इम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जिसको हम सी०ई०सी० कहते हैं उसके साथ मई और जून, 2008 में कुछ ईशूज के ऊपर कंसैसस हुई है क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ जो स्टेटस हैं विशेषतौर पर राजस्थान और हरियाणा उनको सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटर करती है और हमसे बात करके इस बारे में निर्णय करती है। इसकी आखिरी मीटिंग 7 जनवरी, 2009 को हुई थी और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को कन्स्ट्रक्शन सेटीरिथल माईनर मिनरल के लिए डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में 600 हेक्टेयर में करने की इजाजत दी है। Vide orders dated 8th October, 2009 however, Sir, there is a condition attached to it that the actual mining can commence only with the simultaneous commencement of work on restoration and rehabilitation of the old mines. We have already engaged consultants for preparation of a detailed rehabilitation and restoration plan. Sir, hopefully this shall be ready by 31st March, 2010. We will have to submit it to Centrally Empowered Committee as the Supreme Court has directed. Then it will be sent to the MoEFs i.e. Ministry of Environment and Forests for their approval. Once they will approve it then that it will go to the Supreme Court then they approve it. Then only it can start. Sir, I also want to tell the Hon'ble Member with your permission that Supreme Court has agreed in principal to consider mining over an area of 1500 acres in district of Gurgaon and Mewat but Sir, no final approval has come. It will only be given after assessing the compliance of prescribed norms in respect of the earlier portion in the Faridabad District.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिटेल् में रिप्लाई दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बंद क्यों की? इनका जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, एनवायर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और माईन्स का डिपार्टमेंट है क्या इनके कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो नोटिफिकेशन इशू की। एक बार माईनर मिनरल्स की और दूसरी बार मेजर मिनरल्स की। उनकी नोटिफिकेशन आयी कि अगर आपकी पांच हेक्टेयर से ऊपर की क्वैरी है तो आपको उनसे क्लीयरेंस लेने की जरूरत है और अगर इससे नीचे की क्वैरी है तो फिर उन दोनों विभागों से क्लीयरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सर, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर और प्लान बनाकर देना था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने वह प्लान बनाकर दी? सर, दोनों बार यह प्लान न देने की वजह से सुप्रीमकोर्ट ने उन माईन्स को बंद किया। स्पीकर सर, दूसरा सवाल मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का या ऑफिसर्स का जो लैकलस्टर एटीट्यूट रहा, क्या वह उसकी भी देखभाल करेंगे कि किस कारण ये बंद की गयी हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको बंद किया है वह एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री की क्लीयरेंस न देने की वजह से बंद किया है। सर, इसके अगेन्स्ट जो काम किया गया वह यह किया गया कि प्लाट बना दिए गए और कह दिया गया कि पांच हैक्टेयर से या उससे भी कम के प्लाट दे दें और वह दे दिए गए। इसके बावजूद एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्लीयरेंस न होने की वजह से वह बाद में बंद हो गयी। सर, बार-बार इस तरह से इस्केप सूट बूढ़ने के बजाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन करके एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री ने जो इनको गार्डललाईज दी है उसके मुताबिक काम करते ? अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे स्टेट के रेवेन्यू का लोस भी होगा और हर चीज महंगी भी मिलेगी। अब जब हरियाणा प्रदेश में माईनर और मेजर दोनों मिनरल्स माईज बंद हो गयी है तो इस स्थिति के अंदर हरियाणा में जो लोग मकान बनाते हैं या सरकार कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करेगी तो क्या यह मैटीरियल मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो यह बाहर से लाना पड़ेगा ? अगर यह बाहर से लाएंगे तो क्या यह महंगा नहीं मिलेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : श्री सर, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। चार पांच प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। इनकी जो जिज्ञासा है और जो इनके प्रश्न हैं उसके बारे में प्रान्त के लोग भी जानना चाहते हैं। जो चौधरी सम्पत सिंह जी ने प्रश्न पूछे हैं उनका संक्षिप्त समय में मैं जबाब देने का प्रयास करूंगा। एक बात इनकी वाजिब है कि माईनिंग ऐक्टिविटीज बंद होने से प्राकृतिक तौर से कंस्ट्रक्शन मैटीरियल की कीमत ऊपर जाती है। उन्होंने माईज रेवेन्यू की चर्चा की। मैं अपना जवाब भी सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहूंगा। सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक ट्रांसपेरेन्ट माईज ऑक्शन पोलिसी की हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरुआत की। यह बात सच है और चौधरी सम्पत सिंह को भी मालूम है कि एक समय ऐसा था कि जब कुछ विशेष विपक्षी दलों की सरकार हरियाणा के अंदर थी तो उस समय कुछ चहेते लोगों को एक विशेष तरीके से माईन्ज दे दी जाती थी। यह बात आंकड़ों के अंदर भी रिफ्लेक्टिड है। सर, 2000-01 से लेकर 2004-05 के बीच पांच सालों में माईन्ज का कुल रेवेन्यू 536 करोड़ 7 लाख रुपये था। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन को विशेष तौर से दो साल के आंकड़े देना चाहता हूँ। 2003-04 के अंदर माईन्ज का कुल रेवेन्यू केवल 77 करोड़ 67 लाख रुपये था, 2004-05 में जब मेरे काबिल साथी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनकी सरकार गयी और आखिर में जब इनकी सरकार का साल था उस समय माईंस का 92 करोड़ 4 लाख रुपये रेवेन्यू आया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार मार्च, 2005 में आई और उसके बाद यह रेवेन्यू मात्र एक वर्ष की अवधि में 92 करोड़ 4 लाख से बढ़कर 153 करोड़ 34 लाख रुपये का आया। यह सौधने की बात है। (विघ्न) सर, 2006-07 में वह थोड़ा चटकर 136 करोड़ 26 लाख रुपये हो गया जो कि तकरीबन 15 करोड़ रुपये कम आया। 2007-08 में 215 करोड़ 70 लाख हो गया और वर्ष 2008-09 में क्योंकि 28 फरवरी, 2009 के बाद माईंस बंद हो गई इसलिए रेवेन्यू 195 करोड़ 24 लाख रुपये आया और जनवरी, 2010 में 226 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया। It is all time high sir यानी कि हमारे पांच साल के कार्यकाल में 926 करोड़ 54 लाख और इनके पांच साल के कार्यकाल में 536.07 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार माईन्ज से इतना ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा के आम जनमानस की भलाई के लिए लेकर आई, जो कि सरकार की मंशा को कहीं न कहीं बताता है। मेरे काबिल साथी ने 3-4 बड़े ही वाजिब सवाल उठाये हैं वह सच है कि जैसे ही माईन्ज का रेवेन्यू बढ़ा। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन ऑवर है, ये इसमें क्वेश्चन का जवाब दें, भाषण न दें। (विघ्न)

Mr. Speaker : Is it the way Arora Sahab ? ये जवाब ही दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं माननीय सदस्य संपत सिंह जी की सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहा हूँ। (विघ्न) He has asked it in his supplementary and I am answering that. सर, कई बार जब किसी की पोल खुलती है तो पीड़ा होती है उसका भेरे पास कोई हल नहीं है। मुझसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या माइज के बंद होने से कंस्ट्रक्शन मैटीरियल की कॉस्ट बढ़ जायेगी तो इसमें मेरा जवाब है हाँ सर, माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात को खुद मॉनिटर करता है और उनके लेटेस्ट ऑर्डर हैं और उन्होंने हमारे प्रदेश के साथ ही राजस्थान की माइनिंग भी बंद की है। माननीय सदस्य ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या कोई डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की कमी रही है या एक दशक से ज्यादा समय तक क्या प्रोपर माइनिंग नहीं की गई, ये दो तीन बातें रैज की गई और मेरा इसके बारे में जवाब है कि पूरा जो दिल्ली के आसपास अरावली का इलाका है, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, हम किसी एक फैक्टर को थिन प्वायंट तो कर नहीं सकते। पूरे अरावली का जो इलाका है उस इलाके को बचाने के लिए और दिल्ली के धारों तरफ के तीनों राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इन्फ्रोजेक्ट को मॉन्टर करने का सलूत प्रयास सुप्रीम कोर्ट का है और एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह भी जानने की कोशिश की कि हरियाणा सरकार इसके लिए क्या कारगर कदम उठायेगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 9 डिफरेंट स्टैप्स हरियाणा की मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने लिये हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन को और जो माननीय सदस्य हैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या लॉग टर्म मेजर इन्वीयर्ड कमेटी के अलावा हम ले रहे हैं वे स्टैप्स पढ़कर बताना चाहूंगा, इनमें लिखा है कि-

“It is for the first time that any State has taken up a holistic approach to address the concerns arising on account of mining operations on a long term basis. The State Government has taken a number of important decisions in this direction. These are:

- i) A decision was taken at the level of Council of Ministers in its meeting held on 21.08.2009 to ban mining of major minerals in the districts of Faridabad and Mewat for a period of 10 years;
- ii) A decision to undertake State controlled mining of construction material over a limited area of 600 hectares in the district of Faridabad out of total mineral bearing area of 6700 hectares, and 1500 hectares in the district of Gurgaon and Mewat out of the total mineral bearing area of approximately 23000 hectares following extensive discussion and consensus with the CEC;
- iii) Notified a ‘Scheme of Mining’ for the district of Gurgaon and Mewat (which will also be extended to district of Gurgaon and Mewat) consisting of the detailed guidelines for grant of mining contract/leases, establishment of an ‘Aravalli Rehabilitation Fund’ and constitution of a Monitoring Committee to monitor that the mining operations over the limited areas are carried out in compliance of the EMPs for these areas;

श्री अध्यक्ष : बस, काफी लम्बा जवाब हो गया। इतना ही काफी है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, then you can ask the Member to come to me because he wanted to know that.

Smt. Kiran Chaudhary : Hon'ble Speaker Sir, I would like to ask the Hon'ble Minister that the 600 hectares which have been said by the Haryana Government will be identified for mining purposes, have those been identified yet or not? Secondly, what action is being taken for the water depletion that is happening in such a fast pace because of these mining activities, the whole of the water table has gone down drastically. So, what steps are taken by the Government to ameliorate that. The workers who have been rendered jobless for closure of mines for example in my area - Khanak in Tosham and Dadam. What measures are going to be taken by the Government to rehabilitate those mine mazdoors and labourers because their rozi-roti, their entire livelihood is dependent upon that.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, since you are permitting the Members to ask four-four questions in one supplementary then I will have to give long answers. As far as the first questions of the Hon'ble Member is concerned, I want to say that the initial area has been identified but the identification is subject to clearance by the Centrally Empowered Committee that has been appointed by the Supreme Court then it goes to the Ministry of Environment and Forests. Finally, it is submitted to the Supreme Court. Once they give the clearance then only an area is deemed to be cleared. As far as second and third questions are concerned, they are separate questions and a separate notice needs to be given.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताया है कि रेवेन्यू बढ़ा है। मेरा मंत्री जी से इसी बारे में सवाल है। एक तो मंत्री जी यह बतायें कि वर्ष 2000 से पहले कितना रेवेन्यू आता था ? दूसरे आज यहगाई की मार पड़ रही है और सरकार पैसा कमाने के लिए नहीं होती। पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार होती है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रेत का ट्रक पहले 2500 रुपये में मिलता था आज वह 11000 रुपये में मिलता है और बजरी का ट्रक जो पहले 3500 रुपये में आता था आज वह 14000 रुपये में आता है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this is a separate question. So, a separate notice needs to be given. (interruptions)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यह इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंत्री जी स्टेट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। यह प्रश्न सैप्रेट थोड़ा ही है। मंत्री जी खुद बता रहे हैं कि इतना रेवेन्यू बढ़ा है। यह प्रश्न भी इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह मामला प्राईस से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मंत्री जी यह बतायें कि कितना रेवेन्यू बढ़ा है ? यहगाई की मार तो लोगों पर पड़ रही है। (दिघ्न)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे तभी ये खानें बन्द की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक खानों में कितनी चोरी हुई है, कितने मुकदमे दर्ज हुये हैं इस बारे में मंत्री जी बतायें? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए उसके बाद फॉरेस्ट एरियाज में पिछले पांच साल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों कि अवहेलना कितनी हुई है और अवैध निर्माण भुइगांव और फरीदाबाद में फॉरेस्ट एरिया में कितने हुए हैं? इस बारे में मंत्री जी बतायें।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this is also a separate question. So, a separate notice needs to be given.

श्री विशानलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये रेतें और बजरी के ठेके दिए जाते हैं उससे सरकार तो ठेकेदार से पैसा ले लेती है और ठेकेदार उस रेतें और बजरी से पैसे कमा लेता है लेकिन जिस किसान की जमीन से वह रेत उदाया जाता है उसको क्या मिलता है इस बारे में मंत्री जी बतायें ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this is also a separate question. So, a separate notice needs to be given.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं आया इसलिए मैं वही सवाल करने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि सुप्रीमकोर्ट को आर्डर देना पड़ा था। इन्वॉयरनमेंट मिनिस्ट्री की क्लीयरेंस नहीं ली हुई थी। इन्वॉयरनमेंट मिनिस्ट्री की थायलेशन डिपार्टमेंट कर रहा था। क्या उसी की वजह से तो ये क्वैरीज बन्द नहीं हुई ? मैंने पहले पूछा था। इन्वॉयरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक माइनिंग माइनिंग के लिए और एक मेजर माइनिंग के लिए नोटिफिकेशन 14 सितम्बर, 2006 और एक उससे पहले 1994 में हुई थी। उस समय जो ये दोनों नोटिफिकेशन हुई थी क्या उसके बाद सरकार कोई पोलिसी नहीं बना सकती थी ? इतना लम्बा पीरियड हो गया है लेकिन कोई पोलिसी नहीं बनाई गई। मैं यह कह रहा था कि इसमें डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके कितनी जल्दी ये पोलिसी बनाएंगे। हमारी सरकार आने के बाद रैवेन्यू बढ़ा है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन जो 100 क्वैरीज बन्द हुई हैं अगर ये बन्द न हुई होती तो रैवेन्यू और बढ़ जाता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : माननीय सदस्य की जिज्ञासा और चिन्ता दोनों वाजिब हैं। यह सच है कि पिछले एक से डेढ़ दशक में जब ये मार्इन्ज खालू की गई थी तो इन्वॉयरनमेंट क्लीयरेंस नहीं थी। ये सारी नोटिफिकेशन जो समय-समय पर जारी हुई हैं उनका सम्पूर्ण निर्वहन नहीं हो पाया था। इसलिए मैं बता रहा था, जब आपने कहा कि हरियाणा सरकार ने अब एक होलिरिटिक पोलिसी बनाई है उसमें हमने 9 भिन्न-भिन्न कदम उठाए हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, इस बारे में एक माननीय सदस्य ने प्रश्न भी पूछा था हालांकि यह पृथक प्रश्न है कि अगर कोई लैंड ओनर है और अगर उसकी जमीन जाती है तो 10 परसेंट लीज अमाउंट था जो कम्पनसेशन जमीन का मालिक लीज होल्डर से सैटल करे, चाहे 100 की 100 परसेंट ही सैटल कर ले वह उसकी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन दोनों नोटिफिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है तो हमने जो होलिरिटिक एप्रोच बनाई है उसके हिसाब से सुप्रीमकोर्ट की सेंटली इम्पॉवर्ड कमेटी निर्धारित है जिसके मुताबिक ग्रीन बैंच निर्णय करता है। हर वह प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे चाहे वह 600 एकड़ का प्रोजेक्ट

बनाएँ और चाहे 1500 एकड़ का बनाएँ, उन सबके केस सेंट्रली इम्पोर्टर्ड कमेटी और मिनिस्ट्री आफ इन्वॉयरनमेंट एण्ड फोरेस्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। जब वहाँ से फाइनली क्लीयरेंस मिल जाएगी, उसके बाद ही उस पर माइनिंग सम्भव हो पाएगी। (विष्णु)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार के काबिल मंत्री ने रेवेन्यू को बढ़ाने के आंकड़े हाउस के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया है यह बहुत बढ़िया बात है। सरकार धन कमाने के लिए नहीं होती बल्कि लोगों के हितार्थ काम करने के लिए होती है। आज हजारों लोग रोजी रोटी को महंरूम हो गए हैं। हजारों लोगों के बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हजारों लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो क्वेरीज बन्द हुई हैं उनमें काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार ने कोई बन्दोबस्त किया है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले ही श्रीमती किरण चौधरी जी ने पूछा है। अजय चौटाला जी भी वही प्रश्न दोहरा रहे हैं। माइन्ज के वर्कर्स की रिहैबिलिटेशन पृथक प्रश्न है। माननीय सदस्या जैसे ही यह पृथक सवाल पूछेंगी हम पूरी इन्फर्मेशन कलेक्ट करके सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय किरण चौधरी जी ने जो विन्ता जाहिर की है, अजय जी ने उसको दोहराया है उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। हमें मालूम है कि गरीब मजदूर की रिहैबिलिटेशन आवश्यक है परन्तु ये सारा डाटा इस सवाल से सीधा जुड़ा नहीं था इसलिए उपलब्ध नहीं है। आप लिखकर मेरे पास भिजवा दें, अजय सिंह चौटाला भी मेरे पास लिखकर भिजवा देंगे, मैं इनको लिखकर जवाब भिजवा दूंगा।

Construction of New Road

* 18 Shri Krishan Lal Panwar : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a new road from Village Sutana, Distt. Panipat to Thermal Plant upto Assandh Road; if so, the time by which the said road is likely to be constructed?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस जवाब पर ये पुनर्विचार करें क्योंकि सुताना गांव के साथ में थर्मल प्लांट की 700 एकड़ जमीन में ऐश डेक है। थर्मल प्लांट की सारी ऐश पानी के साथ मिक्स होकर वहां पर स्टोर होती है। वहां पर किसान सेम की समस्या से तो पहले ही प्रभावित हैं। सुताना गांव के किसानों को मतलीडा मण्डी में अपनी फसल 10 कि०मी० घूमकर ले जानी पड़ती है। यदि यह डेक कि०मी० का टुकड़ा बना दिया जायेगा तो उनका 10 कि०मी० का चक्कर बच जायेगा। इसी गांव की 700 एकड़ जमीन थर्मल प्लांट में भी एकवायर हो रखी है। अब की बार पैडी सीजन में ऐश डेक लीक होने के कारण वहां के किसानों की पैडी की फसल बह गई थी। मेरी मंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि इस सड़क को बनाने पर आप पुनर्विचार करें ताकि वहां के लोगों का 10 कि०मी० का चक्कर बच जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचार साहब की भावनाओं की कद्र करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नेशनल हाई वे-1 पर संजय चौक पानीपत के बिल्कुल साथ से गुजरने वाली सड़क से सुताना गांव कनेक्ट होता है। हमने एक सड़क नेशनल हाई वे-1 और दूसरी पानीपत-जींद रोड जो स्टेट हाई वे-14 है गानि संजय चौक और स्टेट हाई वे-14 है उसे आलरेडी प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के फेज-8 में मंजूर करवा लिया है, जिसकी लैथ 15.3 कि०मी० है। इस सड़क का कंट्रैक्ट दे दिया गया है और मीके पर काम भी चल रहा है। इस सड़क पर 970 लाख रुपये का खर्चा आयेगा और यह सड़क अप्रैल, 2010 तक बनकर तैयार हो जायेगी। इस सड़क के बनने के बाद फिर भी अगर सुताना गांव के निवासियों को और माननीय सदस्य को लगेगा कि अभी भी तकलीफ है और यह सड़क बननी चाहिए तो इस बारे में माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे देंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूरी लेकर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंचार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वहां दूसरी सड़क बनाई जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप जिस सड़क को बनाने की बात कर रहे हैं वह दूसरे गांवों सुहारी आदि होते हुए मतलौडा निकलती है। मैं तो सुताना से थर्मल प्लांट तक की सड़क बनाने के लिए कह रहा हूँ जो पानीपत से जींद-सफ़ीदा रोड है, उस रोड से मिलाती है और सीधा मतलौडा चली जाती है। इस सड़क के बनने से सुताना गांव के लोगों का मतलौडा सड़क तक 10 कि०मी० का रास्ता कम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं उसका इस सड़क से कोई सारलुक नहीं है मैं तो केवल डेढ़ कि०मी० की सड़क सुताना से थर्मल प्लांट तक बनाने की बात कर रहा हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है उसी पर सुताना गांव भी पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क को बनवा रही है और इस पर 970 लाख रुपये खर्च होंगे। इस सड़क के बनने के बाद अगर सुताना गांव के निवासियों को और माननीय सदस्य को फिर भी लगेगा कि अभी भी तकलीफ है और यह सड़क बननी चाहिए तो इस बारे में माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे देंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूरी लेकर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो बिना निशानदेही के बनाई हुई हैं। (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : रामपाल माजरा जी, प्लीज आप बैठें। आपका यह सवाल रिलेवेंट नहीं है। माजरा साहब, आप इतने सीनियर मੈबर हैं और सवाल भी रिलेवेंट नहीं कर रहे। प्लीज, आप बैठें।

Construction of Swimming Pool

* 137 **Dr. Hari Chand Midha :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any announcement to construct a swimming pool at Jind was made by the Hon'ble Chief Minister five years ago; if so, the time by which the said swimming pool is likely to be constructed?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. However, the announcement for constructing the swimming pool at Jind was made on 11/01/2007 and not five years ago.

The swimming pool is expected to be constructed within a period of two years.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि हमने अपने जवाब में तो बताया है कि दो साल के अंदर यह स्विमिंग पूल बना देंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह स्विमिंग पूल इसी साल 2010-2011 तक बना दिया जायेगा।

डॉ० हरिचन्द्र मिड्डा : स्पीकर सर, मैं जवाब से सन्तुष्ट हूँ।

Maintenance of War Memorials

*** 65 Col. Raghbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to allocate funds separately for the maintenance and upkeep of War Memorials installed at various places in the State ; if so, the details thereof?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir, expenses on maintenance and upkeep of War Memorials are being met from Haryana Defence and Security Relief Fund.

A sum of Rs. 19,40,088/- has been spent on maintenance and upkeep of War Memorials from Haryana Defence and Security Relief Fund so far.

कर्मल रघवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरा सवाल यह था कि क्या वार मेमोरियल के लिए कोई सेपरेट फण्ड सरकार में बनाया है। यह मैं भी जानता हूँ कि अभी तक वार मेमोरियल का मैटेरियल डी०एस०आर० के माध्यम से किया जाता है। स्पीकर सर, वार मेमोरियल हमारे उन वार हीरोज़ की याद में बनाये जाते हैं जिनकी वजह से आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनके अप-कीप और मैटेरियल एक्सट्रा-आर्डिनरी होने चाहिए जब कि ऐसा नहीं है। क्या मंत्री जी कृपा बतलायेंगे कि सरकार इसके लिए क्या अर्रेंजमेंट्स करने जा रही है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य कर्मल साहब ने हरियाणा डिफेंस और सिक्वोरिटी रिलीफ फण्ड के बारे में पूछा है। स्पीकर सर, पंजाब डिफेंस एण्ड सिक्वोरिटी रिलीफ फण्ड, 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब बन गया था और यह रजिस्ट्रार ऑफ फर्ज एण्ड सोसायटी के पास रजिस्टर्ड है। हमारे पास इसके अंदर सर्प्राशिपेंट पैसा अवैलेबल है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से जो पैसा खर्च किया गया है उसकी जानकारी पूरे सदन और कर्मल साहब को दे दी है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन करना चाहूंगा कि इस देश के ऊपर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है और जिन्होंने देश की सेवा की है, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार की वे पहली प्राथमिकता हैं। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर माननीय सदस्य को कोई कोताही का इन्स्टांस मिला, अप-कीप में या मैटेरियल में तो उसे वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को या मुझे लिखकर भेजें। मैं इनको आपके माध्यम से आश्वासन देता हूँ कि एक निर्धारित समय सीमा में हम उसको दुरुस्त करवाकर माननीय सदस्य को लिखित रूप में इस बारे जानकारी भेजेंगे।

कर्नल रघवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वह एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सोल्जर बोर्ड ने मुझे एक थिड्डी लिखी है। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :-

"Bhiwani is the Biggest district in terms of strength of Ex-servicemen and area. The district also pioneers when it comes to Warriors and gallantry awards which is a matter of pride for one and all in the district. Every district has a war memorial to commemorate the heroes of the society and the district. Regrettably the war memorial at Bhiwani is not befitting the sacrifices made by its heroes."

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी प्रपोज़ल है कि भिवानी के वार मेमोरियल स्मारक को दोधारा से बीफिटिंग मैनर में नया बनाया जायेगा क्योंकि जो आज का वार मेमोरियल स्मारक है वह ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसकी न तो कोई मेंटीनेंस करता है और न ही उसे कोई देख सकता है। वार मेमोरियल हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा देते हैं इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या भिवानी के अंदर नया वार मेमोरियल स्मारक बनाने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैंने केवल भिवानी के बारे में नहीं अपितु पश्चिम पूरे हरियाणा के लिए माननीय कर्नल साहब को on the floor of the House कैटेगरीकली आश्वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर वे इस बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे या माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेज दें। जो भी दुरुस्ती वे चाहते हैं, जिस प्रकार की भी वे तरमीम सरकार से चाहते हैं, अगर उसके लिए वे कोई स्पैसिफिक डिज़ाईन चाहते हैं, कोई स्पैसिफिक मैटीरियल इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, कोई स्पैसिफिक एक्स्पेंशन वे चाहते हैं, कोई स्पैसिफिक गैलरी उसमें क्रिएट करवाना चाहते हैं और उसके अंदर कोई स्पैसिफिक चीज़ बनवाना चाहते हैं, तो हम उसे रिम्पेशेटिवली कंसीडर करके एक निर्धारित समय-सीमा में बनवाकर और उसका जवाब आपको लिखित रूप में देंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी जब वहाँ पर उसकी 150वीं जयन्ती मनाई जा रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी मंचों से यह घोषणा की थी कि 1857 की क्रांति के जिन शहीद वीरों के बारे में कुछ नहीं किया जा सका उनकी याद में अम्बाला छावनी में हम एक स्मारक बनवायेंगे। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने भी इस प्रकार की घोषणा की। कुमाारी शैलजा, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार ने मेरी मौजूदगी में एक दिन यह कहा था कि वे इस स्मारक के लिए पांच लाख रुपये देंगी लेकिन आज तक पांच पैसे भी सरकार द्वारा इस स्मारक के नाम पर खर्च नहीं किये गये हैं। स्पीकर सर, जैसा अभी हमारे काबिल मंत्री बता रहे थे कि हमारी सरकार इस बारे में बहुत संजीदा है। इस मामले में तो सरकार बिल्कुल गम्भीर नज़र नहीं आती या तो माननीय मुख्यमंत्री अपनी घोषणा को बिल्कुल भूल गये या फिर प्रशासन उनकी घोषणा को गम्भीरता से नहीं ले रहा।

अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपनी जिन्दगी की कुर्बानियाँ दी हैं उस बात को वे सीरियसली न लेकर मजाक में ले रहे हैं यह गलत बात है। हंसी मजाक में उड़ाना उनका अपमान करने के समान है सर। जिन्होंने हमारे देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दीं, (शौर एवं व्यवधान)
This is a serious matter. We should take it seriously.

श्री अध्यक्ष : विज साहब, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि शीरियसली लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठिये तो सही। कोई भी सदस्य बैठे-बैठे कमेंट्स न करे, इससे हाउस चलाने में दिक्कत आती है। हाउस को चलाना हमारा फर्ज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, शहीदों का सम्मान और इस देश के रणबाँकुरे, विवाद का या राजनीतिक मतभेद का प्रश्न ही नहीं हो सकता है। इसीलिए जब कर्नल साहब ने यहाँ पर एक वाजिब सवाल उठाया था तो बड़े खुले दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था और मैंने बड़ी तफसील से माननीय कर्नल साहब को और आपकी अनुमति से पूरे सदन को यह कहा कि इस मामले में हम बिल्कुल उदार हृदय हैं। न केवल कर्नल साहब बल्कि कोई भी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को किसी भी वार मैमोरियल के बारे में कोई सुझाव भेज दें तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम उसको पूरा करेंगे। इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी फौजी हैं और वार मैमोरियल के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जिन्होंने इस देश की सुरक्षा की (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, 1857 में (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am trying to answer, this is not the way, Sir.

Mr. Speaker : He is replying your question. Mr. Vij, let him reply (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, जब विज साहब पाँच बार खड़े हुए मैं पीछे कर गया और मैं बैठ गया। मैंने उनको बोलने के लिए पूरा दस मिनट का समय दिया ताकि वे अपनी स्पीच दे सकें, इसलिए अब उन्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए। दूसरी बात सर, विज साहब मेरे बड़े काबिल सदस्य हैं और मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और हम इकट्ठे भी रहे हैं। जब ये सत्ता पक्ष में थे और हम विपक्ष में थे तब भी रहे हैं। उनको यह भाव्य होगा कि जो आदमी सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में इस सदन में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। (विध्वन) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय कुमारी सीतलजा जी की चर्चा की और उनकी घोषणा की चर्चा की जो कि इनकी मौजूदगी में की थी। मुझे नहीं लगता कि उस बात की यहाँ चर्चा की जानी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने यहाँ पर कही कि 1857 के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका वार मैमोरियल कब तक बनेगा ? इस बारे में कर्नल साहब के प्रश्न में नहीं पूछा गया था और हैंडी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और हो भी नहीं सकती। इसलिए विज साहब अलग से लिख कर भेज दें मैं लिख कर इनको भिजवा दूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he is interrupting me. This is not the way. (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is not possible, Vij Sahib. I allowed you to speak. Now, let him give his reply.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में तो पॉसिटिक्स नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : This is not a matter of politics. This is a matter of war memorials. You have already made your point. I am trying to say something with the permission of the Chair. (Interruptions) We have to have decorum, decency and mutual respect. सर, जैसा मैंने कहा कि हमारे वित्त मंत्री जी स्थव्र एक फौजी रहे हैं और वे देश की सीमाओं की सुरक्षा करके आये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ तक अपने शहीदों के लिए, स्वतंत्रता सैनानियों के लिए, फौजियों के लिए कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। हमारे पास इस समय भी उनके लिए लगभग साढ़े 6 पौने 7 करोड़ रुपये का बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पूरे सदन को यह कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी वार मेमोरियल की आवश्यकता हो, जिस प्रकार के वार मेमोरियल की आवश्यकता हो, जिस प्रकार का मेमोरियल आप चाहें, जहाँ मैटीनेन्स में किसी प्रकार की कोताही हो या कोई विशेष प्रकार की मैटीनेन्स आप चाहते हैं या और कोई साजो-सामान आप चाहते हैं जिससे कि हम शहीदों का सम्मान कर सकें तो इस बारे में हमें सुझाव दें हम उनको अवश्य पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे माननीय सदस्य ने बात कही है, उसके बारे में मंत्री जी ने सही जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, लोग समझते हैं कि आजादी की पहली किंगारी मेरठ से फूटी थी लेकिन इन्होंने अपनी बात बोलते हुए यह बात कही कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पहली किंगारी अम्बाला से फूटी थी, यह बात सही है और इसका सारी दुनिया को पता है। अध्यक्ष महोदय, 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उसमें भी अगर कोई हरियाणा से सदस्य था तो वे अम्बाला से जाला जी थे। यह सब हमारे को मालूम है और इन्हीं चीजों को देखते हुए ही हमने कहा है कि अम्बाला में हम वार मेमोरियल बनवाएंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बात की है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो वार मेमोरियल हमारे भिवानी के अन्दर है जिसकी वर्चा कर्नल साहब ने की है, क्या हमारे को वहाँ पर नई जमीन उपलब्ध करवाकर दी जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया है कि सबसे ज्यादा वहाँ से शहीद हुए हैं और पूरे हरियाणा में से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में वहाँ से ही जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग वहाँ के शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा भिवानी महेन्द्रगढ़ से ही हीरोज बने हैं। मंत्री जी क्या हमें वहाँ पर अलग से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वहाँ पर हम वार-मेमोरियल बनवा सकें ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य जी की भावना से सहमत हूँ। (विघ्न) जब आपका ऐसा रवैया है तो आप कैसे शहीदों का सम्मान करेंगे ? (विघ्न) सर, मैं माननीय सदस्य जी की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस विषय में चाहे किसी भी सम्मानित सदस्य का सुझाव हो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सदन में यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस सवाल के आते ही स्पष्ट आदेश दिए थे कि इस बारे में विपक्ष के और निर्दलीय विधायकों के सबके सजेशन लीजिए। आप हमें इस बारे में लिख कर भेज दीजिए हम जांच करवाकर जो हो सकेगा वह अवश्य कर देंगे।

Property of Haryana Wakf Board

* 102 **Shri Aftab Ahmed** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) the district-wise total property of Haryana Wakf Board in the State;
- (b) whether whole of the property is in the possession of Wakf Board togetherwith the details of the property in illegal possession;
- (c) the steps being taken to vacate property from illegal possession; and
- (d) whether there is any proposal for providing lands for graveyards in the villages and towns in the State of Haryana where Muslim population resides and there is no Wakf Board property exists?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

- (a) Sir, the details of district-wise properties of the Haryana Wakf Board are placed on the table of the House as **Appendix-I**.
- (b) No Sir. The details are placed on the table of the House as **Appendix-II**.
- (c) The Board has filed suits for possession in the Courts for vacation of Wakf properties from illegal possession. Presently, 447 such suits are pending in various Courts. Details of the same are appended as **Appendix-III**. Besides, there are 189 cases in which the Board has issued notices under Section 54 of the Wakf Act, 1995 against illegal occupants/encroachers and in 24 cases, after conducting proper enquiry, the Chief Executive Officer of the Board has already passed order against the encroachers under Section 54 (3) of the Act and referred to the concerned Sub Divisional Magistrates under Section 55 for execution. For rest of the properties, the action is being taken.
- (d) At present there is no policy. However each case will be considered by the Government on receipt of proposal. सर, इसके साथ ही साथ मैं इस सवाल के डी पार्ट में एक लाइन और डालना चाहूंगा। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आदेश दिए हैं कि जहाँ-जहाँ पर आवश्यकता है और हमारे पास जमीन है वहाँ पर हम ग्रेवार्ड्स प्रोवाइड करायेंगे।

Appendix - I

Sr. No.	District	No. of rural properties	No. of urban properties	Total No. of rural & urban Wakf properties	Area of rural Wakf properties as per Gazette notification			Area of urban Wakf properties as per Gazette notification			Total area of Wakf properties		
					Kanal	Marla	Sq. Yds.	Kanal	Marla	Sq. Yds.	Kanal	Marla	Sq. Yds.
1	Ambala	689	386	1075	8960	3	12	1667	17	9	10628	0	21
2	Panchkula	72	29	101	2713	10	21	89	7	17	2802	17	38
3	Karukshetra	697	285	982	16450	15	-	1492	5	16	17943	-	16
4	Karnal	418	309	727	7472	9	-	1376	5	-	8848	14	-
5	Paripat	296	675	971	4690	12	-	7014	12	6	11705	4	6
6	Sonepat	350	419	769	3056	5	-	700	9	9	3756	14	9
7	Faridabad/Fatwal	336	213	549	4541	8	16	469	1	28	5010	9	44
8	Gurgaon	202	44	246	1601	5	-	264	16	12	1866	1	12
9	Mewat(Nuh)	1977	234	2211	32151	8	-	1545	8	-	33696	16	-
10	Rewari	171	82	253	1954	5	-	279	30	-	2234	5	-
11	Mohindergarh	98	252	350	823	6	-	14576	6	-	15399	12	-
12	Rohtak	160	135	295	1767	15	-	532	14	5	2300	9	5
13	Jhajjar	178	108	286	2096	5	-	45	16	25	2142	1	25
14	Jind	345	80	425	2549	7	-	351	2	-	2900	9	-
15	Sirsa	362	161	523	8961	1	11	1339	4	21	10300	5	32
16	Fatehabad	269	47	316	8762	19	23	1106	16	9	9869	15	32
17	Hissar	397	507	904	5388	7	-	1854	3	16	7242	10	16
18	Bhiwani	263	123	386	3450	14	-	974	13	6	4425	7	6
19	Kaithal	379	162	541	6886	18	16	1449	17	7	8336	15	23
20	Yaruna Nagar	525	58	583	4383	17	19	868	8	-	8752	5	19
Grand Total		8184	4309	12493	129153	189	118	37989	199	186	167153	168	304

Appendix-II

1	2	3	4	5
Sr. No.	Name of District	No. of Wakf properties in the possession of Wakf Board	No. of properties under encroachment	Grand total of column No. (3) & (4)
1	Ambala	1019	56	1075
2	Panchkula	79	22	101
3	Yamuna Nagar	580	3	583
4	Kurukshetra	911	71	982
5	Kaithal	530	11	541
6	Hisar	745	159	904
7	Sirsa	460	63	523
8	Fatehabad	296	20	316
9	Bhiwani	312	74	386
10	Karnal	702	25	727
11	Panipat	944	27	971
12	Sonepat	640	129	769
13	Rohtak	218	77	295
14	Jhajjar	189	97	286
15	Gurgaon and Mewat	2428	29	2457
16	Faridabad and Palwal	532	17	549
17	Rewari	249	4	253
18	Mohindergarh at Narnaul	324	26	350
19	Jind	422	3	425
Total		11580	913	12493

* About 450 Acre Wakf lands are under encroachment. Exact area under encroachment is being worked out by demarcation.

Appendix-III

Sr. No.	Name of the District	Suit for possession filed by the Board
1	Ambala	58
2	Yamuna Nagar	71
3	Kurukshetra	44
4	Rewari	41
5	Hissar	7
6	Bhiwani	7
7	Sirsa	14
8	Jind	3
9	Tohana	22
10	Kaithal	31
11	Karnal	32
12	Panipat	13
13	Sonepat	59
14	Rohtak & Jhajjar	19
15	Palwal & Faridabad	19
16	Gurgaon/Mewat	7
Total cases		447

श्री आज़ताब अहमद : स्पीकर सर, वक्फ प्रापर्टी एक ऐसी प्रापर्टी होती है जिसमें आदमी का अपना इन्ट्रस्ट तो होता नहीं है। आज जमीन के भाव बहुत बढ़ चुके हैं जिसके कारण the department is not able to handle these cases in such a manner. जहां उनके पक्ष को सही रखा जाए। इस कारण से कोर्ट में वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित ज्यादातर केसिज में लीगली हार हो जाती है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई मकैनिज्म है जिससे उसको सुदृढ़ किया जाए और रिस्पॉसिबिलिटी फिक्स की जाए ? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी केसिज हैं उनको इकट्ठा किया जाए। इस तरह के केसिज तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सोल्व हो सकते हैं क्योंकि वक्फ ऐक्ट अब बहुत ही स्ट्रॉंगली आ चुका है जिससे इललीगल पोजेशंस को बैकेट करवाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाएगा क्योंकि अभी तक तो यह देखा गया है कोर्ट में जाकर के वक्फ

बोर्ड अपने केस हार जाता है और प्राईवेट पार्टी जीत जाती है ? प्राईवेट पार्टी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने से काफी फायदा हो जाता है। सर, वक्फ बोर्ड का रवैया इस मामले में बड़ा लचीला होता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य आफताब अहमद जी की चिन्ता के साथ अपने आपको भी जोड़ता हूँ। यह सच है कि वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी की बैटर मैनेजमेंट के बारे में आजादी के बाद लगातार प्रश्न उठते रहे हैं और कई बार यह भी देखा गया है कि वक्फ प्रोपर्टीज पर इललीगल एनक्रोचमेंट्स हो जाती हैं और उन पर इफैक्टिव कार्यवाही नहीं होती। हमने सबसे पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास जो प्रोपर्टीज हैं उसका फ्रेश सर्वे करने के लिए आर्डर कर दिए हैं। बहुत सारी नयी प्रोपर्टीज भी इसके अंदर आईडेंटिफाई होने का प्रोसेस इस समय ऑन है। जहां तक लिटीगेशन का प्रश्न है हमने उसके लिए बाकायदा एक-एक जिले की सैपरेट डिटेल्ड अनेक्चर बनाकर माननीय सदस्य को दी हैं। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूंगा कि हम कम से कम वक्फ प्रोपर्टीज की सुरक्षा को लेकर सजग हैं। जहां पर माननीय सदस्य को लगे कि कोई अधिकारी कोताही कर रहा है तो आप बताएं। सैकड़ों से भी ज्यादा केसिज हैं अपॉइंटमेंट में भी आपने देखा है कि हजार से भी ज्यादा केसिज हैं इसलिए इनमें से हर केस पर हर समय हम नजर रख सकें, यह संभव नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि अमुक अधिकारी अमुक प्रोपर्टी के अंदर डिफेंस में गड़बड़ कर रहा है या अमुक प्रोपर्टी में जालसाजी या मिलीभगत से गलत ब्यानी की है तो इसके लिए वक्फ बोर्ड के 1995 के ऐक्ट में अपील का प्रावधान है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में हम कार्यवाही करेंगे और अपील भी करेंगे। आप इंडीपेंडेंटली इन्स्टेंस लिखकर दे दें। अगर माननीय सदन के किसी भी सदस्य के नोटिस में इस बारे में कोई बात आए तो यह उसको लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है और बताया है कि वक्फ बोर्ड की 913 प्रोपर्टीज एनक्रोच हैं जबकि 447 प्रोपर्टीज के ही केस सूट फाईल किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो बक़ायदा केसिज रह गए हैं क्या उन पर भी मंत्री जी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा सवाल के 'सी' पार्ट के अंदर हमने बताया कि ये केसिज फाईल हो चुके हैं और बाकी के केसिज के बारे में ऐक्शन लिया जा रहा है। प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी अगर आप लिखकर पूछेंगी कि वह किस स्टेज पर है तो मैं बता पाऊंगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी क्लैक्ट करके आपको भेज दूंगा।

श्रीधरी मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना भी चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कोई सच है तो एक ही बात है कि जो दुनिया में आया है वह एक न एक दिन दुनिया से जाएगा और उसे मरना ही है। सर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने ग्रेवयार्ड देने के लिए प्रोविजन किया है। मैं मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर वक्फ बोर्ड की करीब 600 वर्ग गज जमीन थी और आज भी है। इस जमीन पर श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बुद्धराम का कब्जा था लेकिन जब वही के मुसलमानों ने ऐतराज किया और कहा कि वहां पर हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए स्थल नहीं है, जगह नहीं है तो उनके अनुरोध को मानते हुए उसने उस जगह को खाली कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा प्रश्न करें। Don't give the speech.

चौधरी मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, 600 वर्ग गज जमीन हिसार के अंदर है। इसी तरह से यमुनानगर के अंदर ससोला रोड पर एम.सी. वार्ड नं० 23 में भी जमीन है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह पोसिबल है कि हर एक प्रोपर्टी का हवाला दिया जाए ? आप रैलैवैन्ट क्वेश्चन पूछें।

चौधरी मोहम्मद इलियास : सर, मैं जिलेवाइज अर्ज कर रहा हूँ। सिरसा जिले के अंदर ऐलनाबाद में भी काफी आबादी देहात में मुसलमानों की रहती है। इसी तरह से माधव सिंघाना भी एक गांव ऐलनाबाद में है जहाँ पर काफी मुस्लिम रहते हैं। कागजाना गांव के अंदर भी बहुत मुस्लिम बसते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो सारे स्टेट पर आ गए। इन सभी का मंत्री द्वारा रिप्लाइ देना संभव नहीं है इसलिए आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें।

चौधरी मोहम्मद इलियास : सर, जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों के पास जगह नहीं है। क्या माननीय मंत्री का ऐसा कोई विचार है कि उनको कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाएगी ? स्पीकर सर, क्या मंत्री जी बलाएंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ पर ग्रेवयार्ड के लिए जगह नहीं है क्या वहाँ के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव दिवाराधीन है कि उनको कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाएगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी ने वह सवाल बाकायदा अपने सवाल के 'डी' पार्ट में स्पेसिफिकली पूछा हुआ है और उसका मैं स्पेसिफिक जवाब दे चुका हूँ, वह सवाल दोबारा माननीय सदस्य पढ़ लें तो वही जवाब है।

चौधरी आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ बड़ी बड़ी औद्योगिक नगरियाँ हैं, उनमें से फरीदाबाद और पानीपत में हमारी कब्रिस्तान के लिए भूमि की मांग पिछले कई सालों से लम्बित है और वहाँ कब्रिस्तान सरकार की जमीन से दिये जाने हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि उसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके सरकार कम से कम कब्रिस्तान के लिए तो जमीन दें, यह मेरा भी सरकार से अनुरोध है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : जहाँ तक कब्रिस्तान के लिए जमीन देने की व्यवस्था करने का प्रश्न है जैसा माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इलियास जी ने कहा या श्री आफताब अहमद जी ने कहा। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यह डिबेट या विवाद का प्रश्न है ही नहीं। हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक स्टेच्यूटरी बॉडी है और कब्रिस्तान के लिए जहाँ भी जमीन है वहाँ हम देने के लिए तैयार हैं। अगर ये लगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है तो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ हमारे नाइनैरिटीज के भाइयों के लिए कब्रिस्तान की आवश्यकता है उनके लिए नगर पालिका या पंचायत के माध्यम से या किसी भी विभाग की जमीन हो, वहाँ हम जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। स्पेसिफिक इन्स्टांस लिखकर भेजेंगे तो हम उसकी जांच करण के सुनिश्चित करेंगे कि उसका हल निकाल सके।

Upgradation of Schools

* 86 **Shri Sher Singh Barshami** : Will the Education Minister be pleased to state —

- (a) the total number of Primary, Middle and High schools upgraded in Ladwa Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and
- (b) whether there is any proposal under consideration to upgrade the Primary to Middle, Middle to High and High to Secondary schools during the current and next financial year 2010-2011 ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail):

- (a) Sir, The total number of schools upgraded in Ladwa Assembly Constituency during the period from 1.4.2005 till date are : Primary School to Middle School-twenty five; Middle School to High School-one; and High School to Senior Secondary School-two.
- (b) The upgradation norms for schools are under revision. Further upgradation of Schools in Ladwa Assembly Constituency would be considered after finalisation of revised norms.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब ये स्कूल अपग्रेड किए गए इसके लिए क्या क्राइटेरिया ऐडोप्ट किया गया ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातन्हैल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूलों को अपग्रेड करने के जो नॉर्म हैं उसमें प्राइमरी टू मिडिल के लिए 150 students and at least 25 students studying in the class 5th for the last two years. 150 students for middle to high i.e. 6th to 8th class and at least 50 students studying in the 8th class for the last two years and 150 students for high to secondary i.e. 9th and 10th class as per the record of the school. As per the record of the school education, the land area for the primary to middle school is about one acre, middle to high is about two acres and high to senior secondary is two acres. As far as building norms are concerned, for primary to middle school is 8 rooms with the condition of one room per section for the education purpose and the middle to high, 10 rooms and for high to senior secondary, 12 rooms are required.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय जो स्कूल उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे वे सभी स्कूल अपग्रेड किए जा चुके हैं यदि किए जा चुके हैं तो उनके नाम बताने का कष्ट करें ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातन्हैल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जो स्कूल प्राइमरी से मिडिल अपग्रेड हुए हैं वे 25 हैं। जिसमें पहला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अन्टेड़ी जिसे 2006 में अपग्रेड किया गया। दूसरा जी०एम०एस० बदरपुर और तीसरा इनके अपने गांव में जी०एम०एस० बड़शामी हैं, चौथा जी०एम०एस० बरछपुर स्कूल अपग्रेड किया गया है। इसी प्रकार से

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

जी०एम०एस० बरौदी, जी०एम०एस० बरतौली, जी.एम.एस. बहलौरपुर, जी०एम०एस० भूतमाजरा, जी०एम०एस० बुद्धा, जी०एम०एस० चालींदी, जी०एम०एस० छपरा, जी०एम०एस० झरौला, जी०एम०एस० हलालपुर, जी०एम०एस० गोबिन्दगढ़, जी०एम०एस० जैनपुरा, जी०एम०एस० जंधेड़ा और जी०एम०एस० कलीराव। मिडिल से हाई स्कूल जो अपग्रेड किए गए हैं वे हैं लाडवा, मुनारपुर, सलेमपुर, संभलखेड़ा, सींती, सुल्तानपुर, झूरा और लोहारा हैं। इसी प्रकार से हाई से सीनियर सैकेंडरी स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं, वे हैं गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल बाणी और गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल बरौदा।

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, I would like to request the Hon'ble Minister that in her reply she has said that the up-gradation norms of schools are under revision and further up-gradation schools will be considered after the finalization of revise norms. As you know well Sir, that education is one of the primary sectors of our Government. That is why, the Government School attach great deal of priority to it. I would like to ask the Hon'ble Minister when these revise norms are going to be finalized and what is the time bound period? Secondly Sir, she had announced that in every block model schools are going to be put in. So, I would also like to ask her through your goodself by what time these model schools will also be started.

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble member as per the revising norms that the school building having more than one storey should provide one ramp and stair case at least six feet width. The reason to revise these norms is because the Right to Education Act is going to be implemented from 1st April, 2010. So Data regarding the up-gradation of schools from the Primary to Middle, Middle to High and High to Senior Secondary schools have been analysed during 2009-10 and after examining it was found that the up-gradation of these schools are highly swepted. The data clearly shows that in some of the places numbers of the schools have been upgraded and in some of the places number of the schools up-gradation were less that's why we have decided that this policy regarding the revision of norms will be finalized by 30th of April, 2010. Sir, second query she has asked about the model schools. As we are considering and cases are pending, we will decided it.

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I just wanted to know from the Hon'ble Minister as the concerned minister has not replied my question.

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री शेर सिंह बड़झामी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो स्कूल वर्ष 2005 से आज तक अपग्रेडेशन का क्राईटेरिया फुलफिल करते थे, क्या ये सारे स्कूल अपग्रेड कर दिए गये हैं या जो क्राईटेरिया फुलफिल करते हैं उनको अपग्रेड किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, इनकी लाडवा कांस्टीच्यूरंसी के जितने भी स्कूल अपग्रेडेशन के लिए पेंडिंग हैं उनको नई रिवाइज्ड पॉलिसी बनने के बाद टेक अप करेंगे। अगर आपकी

हमारे पास स्कूल अपग्रेडेशन की एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट आई है और वे शर्तें पूरी करते हैं तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस समय अपग्रेडेशन के लिए जो क्राइटेरिया लागू था और जो स्कूल उस क्राइटेरिया को पूरा करते थे क्या वे सभी स्कूल अपग्रेड किए जा चुके हैं या नहीं। यदि क्राइटेरिया पूरा होने के बाद भी जो स्कूल अपग्रेड नहीं किए गये हैं क्या उनको पहले की शर्तों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस समय अपग्रेडेशन के क्राइटेरिया को रिवाइज कर रहे हैं और पिछले as per norms कंसीडर किए हैं। It depends on the case to case or it is the discretion of the Government for upgradation of the schools we have to take the approval of the F.D. and these cases are pending.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस समय अपग्रेडेशन के लिए जो क्राइटेरिया लागू था और जो स्कूल उस क्राइटेरिया को पूरा करते थे क्या वे सभी स्कूल अपग्रेड किए जा चुके हैं या नहीं या जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : बड़शामी जी, मंत्री जी ने बताया है कि नई पोलिसी आ जायेगी उसके बाद इनको कंसीडर किया जायेगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, लाडवा के अलावा दूसरे जो स्कूल क्राइटेरिया पूरे करते थे क्या उनको भी अपग्रेड किया जायेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, लाडवा के अलावा हमने टोटल स्कूल जो अपग्रेड किए हैं उनके बारे में मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि पूरे स्टेट में हमने जो स्कूल अपग्रेड किए हैं वे 2006-2007 में प्राइमरी से मिडिल 190 स्कूल अपग्रेड किए हैं। इसके अलावा जो स्कूल क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको भी नई पोलिसी के तहत डिस्टाइड करेंगे।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया है कि इन नार्म्स को रिवाइज करने के बाद जो स्कूल रह गये हैं उनको नई पोलिसी के हिसाब से टेक-अप किया जायेगा।

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब वही है कि नई पोलिसी आने के बाद किया जायेगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, लाडवा के अलावा दूसरे जो स्कूल क्राइटेरिया पूरे करते थे क्या उनको भी अपग्रेड किया जायेगा ?

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने एक जगह अपने जवाब में यह कहा कि it is the discretion of the Government. मैं मंत्री महोदय जी से क्लेरिफिकेशन चाहती हूँ

[श्रीमती किरण चौधरी]

कि क्या डिस्ट्रीकशन के हिसाब से स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा या सरकार अपनी मर्जी से स्कूलों को अपग्रेड करती है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि जो स्कूल नार्म्स पूरा करते हैं क्या उनके हिसाब से उनको अपग्रेड नहीं किया जायेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि upgradation depends on case to case और जो भी स्कूल हम अपग्रेड करते हैं उसके लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से एप्रूवल लेनी होती है।

Mr. Speaker : Now the Question Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Upgradation of Schools

* 108. **Shri Rameshwar Dayal :** Will the Education Minister be pleased to state—

- the total number of Primary, Middle and High schools upgradated in Bawal Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and
- whether there is any proposal to upgrade Primary to Middle, Middle to High and High to Sr. Secondary School level during the current and next financial year 2010-2011.

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

- श्रीमान जी, बावल विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में 1-4-2005 से अब तक स्तरोन्नत किए गये विद्यालयों की कुल संख्या प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय - शून्य, माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय-1 तथा उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-5 है।
- विद्यालयों को स्तरोन्नत करने के मापदण्ड संशोधन हेतु विचाराधीन हैं। बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विद्यालयों को, स्तरोन्नत करने के मापदण्ड संशोधित करने उपरांत, विचारा जाएगा।

Punjabi as Second Language

* 76. **Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Education Minister be pleased to state—

- the details of the notification declaring Punjabi as the second language of the State;

- (b) whether this notification fulfills all the required conditions under the law; and
- (c) if the answer to (b) above is in affirmative, then what is the status of Telugu language in the State ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुवकल मातनहेल) :

श्रीमान् जी

- (क) अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई है।
- (ख) जी हाँ,
- (ग) प्रश्न के (ख) एवं (ग) भाग पारस्परिक असम्बन्धित हैं।

अधिसूचना

हरियाणा सरकार

शिक्षा एवं भाषा विभाग

दिनांक 28 जनवरी, 2010

संख्या 1/50-2010 प्रशा०(2).—हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे सूचीबद्ध शासकीय प्रयोजनों में उपयोग किए जाने के लिए पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं,—

- (i) राज्य सरकार तथा इसके कार्यालयों द्वारा पंजाबी भाषा में प्रतिवेदनों को ग्रहण करना ; तथा
- (ii) पंजाबी भाषा तथा पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना।

राजन गुप्ता,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा तथा भाषा विभाग।

*125. **Smt. Sumita Singh** : Will the Environment Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to preserve the environment in the state ; if so, the detail of scheme ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes Sir, The detail of the scheme under consideration of the Government are laid on the table of the House.

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

Detail of Schemes

Government of Haryana have been implementing various schemes for the preservation of environment in the State. At present 5 new schemes are under active consideration of the State Government:-

1. Introduction of Green Buildings concept.

The Environment Department is considering to issue a notification making adoption of the green building concept compulsory for buildings occupying a prescribed minimum floor area/plot area. Action has been initiated to prepare a 'Green Manual' for the State.

2. Preparation of Environmental Action Plan for the Towns of Faridabad and Panipat.

The Central Pollution Control Board has conducted a survey of 88 selected industrial areas /clusters with the help of IIT Delhi and developed a Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI). Faridabad comes at Serial No. 18 and Panipat comes at serial No. 37 in this list of 88 industrial areas /clusters in descending order of CEPI. The State Government has initiated the preparation of remedial action plan for these two towns to restore their environmental quality.

3. Improved System for the disposal of Bio-Medical Waste .

Since it has been found that present arrangement for Bio-Medical Waste disposal is not satisfactory, the Department of Environment has initiated action to prepare a more effective plan of action in consultation with the Health Department.

4. Safe disposal of used/fused and disposed of compact fluorescent lamps (CFL).

The Department of Environment has initiated action to prepare a plan for collection and disposal of used/fused and disposed of Compact Fluorescent Lamps (CFL), with the help of the Municipal Committees.

5. Restructuring of Haryana State Pollution Control Board.

It is felt that with the increased emphasis on environment, there is need for strengthening of the Haryana State Pollution Control Board. The Board is preparing a restructuring plan accordingly.

Crime Against Women

* 83. Shri Ajay Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the yearwise total number of cases registered relating to Crime against women, for the period 2001 to 2009; and

(b) the yearwise number of case registered, for the crime of female foeticide during the period 2001 to 2009 ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

बिन्दु (क)

महिलाओं के विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों

अपराध का शीर्ष	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	3391	4383	4132	4160	4107	4660	4756	5095	5415

बिन्दु (ख)

कन्या भ्रूण हत्या के दर्ज मुकदमों

अपराध का शीर्ष	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
कन्या भ्रूण हत्या अपराध	26	25	29	36	44	47	30	45	44

To Regularise Jhuggi/Basties

* 92. Shri Krishan Pal Gurjar : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the Jhuggi/Basties of Faridabad; if so, the time by which these Jhuggi/Basties are likely to be regularized; and
- whether there is any proposal under consideration of the Government to start development works in the above said Jhuggi/Basties ?

विजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

- नगर निगम, फरीदाबाद, फरीदाबाद में झुग्गी-बास्तियों को पुनर्वासित / पुनर्स्थापित करने के लिए योजनाएं तैयार करता आ रहा है।
- उपरोक्त 'क' के दृष्टिगत, झुग्गी / बास्तियों में विकास कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Facility of Post-mortem

* 120. **Shri Kali Ram** : Will the Health Minister be pleased to state —

whether there is a provision of any room for post-mortem in Government Hospital. Safidon if so, the reason for not doing post-mortem in the above said hospital ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : हां श्रीमान जी, सरकारी अस्पताल, सफीदों में पोस्टमार्टम के लिए एक कमरा उपलब्ध है। अस्पताल में अब पोस्टमार्टम कार्य करने की व्यवस्था कर ली गई है।

Posting of Principal in I.T.I., Kalka at Bitna

* 115. **Shri Pradeep Chaudhry** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether the post of Principal in ITI Kalka at Bitna is lying vacant; if so, the time by which this post is likely to be filled up;
- whether the posts of Group Instructor and instructors in ITI Kalka are lying vacant; if so, the time by which these posts are likely to be filled up; and
- whether the Heavy Vehicle Motor Mechanic course is being run in ITI Kalka ; if so, whether any practical training is also being imparted to the students of this course ?

मुख्यमंत्री (श्री सूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- हां, श्रीमान जी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालका एट बिटना में प्रधानाचार्य का पद 1.8.2009 से रिक्त है तथापि, आदेश दिनांक 8.3.2010 अनुसार श्री राम कुमार की नियुक्ति प्रधानाचार्य आई०टी०आई० कालका के पद पर कर दी गई है।
- हां, श्रीमान जी, वर्ग अनुदेशक के 3 पद तथा व्यवसाय अनुदेशक के 30 पदों में से 2 पद वर्ग अनुदेशक तथा 16 पद व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त हैं। इन पदों को शीघ्र ही भरा जाना सम्भावित है।
- मैकेनिक रिपेयर एण्ड मेन्टेनेंस अंतर्ग हैवी व्हीकल व्यवसाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालका में चल रहा है। इस व्यवसाय के छात्रों को अधिकतर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में ही दिया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध हरियाणा परिवहन कार्यशाला, चण्डीगढ़ में भी किया गया है, जब तक संस्थान में इस व्यवसाय की पूर्ण मशीनरी उपलब्ध नहीं हो जाती।

Construction of New Road

* 145. **Shri Charanjeet Singh** : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the names of new roads constructed in Kalanwali constituency during the period from 2005 to 2009 togetherwith the total amount incurred thereon?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री, (श्री रणदीप सिंह सूरजेवाला) : कालांबली निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2005-2009 के दौरान जिन नई सड़कों का निर्माण हुआ, उनके नाम निम्नलिखित हैं :-

क्र० सं०	सड़क का नाम
1.	तारुआना में तारुआना कालांबली-रोड़ी लिंक सड़क
2.	लोक निर्माण विभाग सड़क से गुरुद्वारा बड़ागुडा लिंक सड़क
3.	धिराज से मलझारी पुल तक लिंक सड़क
4.	बड़ागुडा से धवन-भगुं लिंक सड़क
5.	भीमा से रोहन तक लिंक सड़क
6.	शदराना से चकेरियां तक लिंक सड़क
7.	बीरुवाला गुड्डा से सुधाखेड़ा तक लिंक सड़क
8.	दादू से तखतमल तक लिंक सड़क
9.	दादू से कमल तक लिंक सड़क
10.	तारुआना से कलुआना छोटे पुल तक लिंक सड़क
11.	आनन्दगढ़ से रघुआना
12.	पक्का से कोरिआना पंजाब सीमा तक लिंक सड़क
13.	रघुआना से साहूबाला-1 तक लिंक सड़क
14.	रोड़ी में अनाज मण्डी की सड़कों को जोड़ना
15.	नरेल खेड़ा से भावदीन तक लिंक सड़क
16.	फरवेम कलां से दरवी तक लिंक सड़क
17.	मुख्य सड़क से वाटर वर्क नगोकी तक लिंक सड़क
18.	छत्तरगढ़ पट्टी झोम्पड़ा

इन सड़कों के निर्माण पर 314.93 लाख रुपये की कुल राशि खर्च हुई।

Occupants of the Leasehold Houses and Plots

* 149. Smt. Kavita Jain : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give ownership by making registries in favour of these occupants of the plots of shops and houses given to them on lease by the Municipal Council, Sonapat; and
- (b) if so, the time by which the registries are likely to be started together with the rate at which the said registries will be executed; and if not, the reasons thereof ?

विजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

- (क) यदि एडेवार्सों को अलाट भूमि / भवन और चुकानों का मासिक किराया 500/- रु० से कम है और वह सम्पत्ति लम्बे समय से उनके कब्जे में है तो सरकार की इस बारे में नीति है।
- (ख) नगरपरिषद सोनीपत ने इस प्रकार की सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के लिये एक प्रस्ताव पारित किया है। उसे नीति के अनुसार विचार जायेगा।

To Segregate the load of Domestic Agricultural Sectors

* 5. Shri Ram Pal Majra : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any scheme to segregate the load of domestic sector and agricultural sector for the distribution of electricity in the State; if so, the time by which the aforesaid scheme is likely to be implemented togetherwith the circlewise details thereof?

विजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : हां श्रीमान, राज्य में ग्रामीण धरेलू तथा कृषि पावर लोड को अलग करने की एक योजना लागू की गई है। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सर्कलानुसार नए फीडरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सर्कल का नाम	स्थापित किए जाने वाले फीडरों की संख्या	अलग करने का कार्य पूरा होने वाले फीडरों की संख्या	फीडरों की संख्या जिन पर कार्य प्रगति पर है	पूरा होने की सम्भावित तिथि
--------------	--	---	--	----------------------------

उ०ह०वि०वि०नि०

अम्बाला	63	63	--	--
यमुनानगर	84	84	--	--
कुरुक्षेत्र	87	87	--	--

1	2	3	4	5
कैथल	69	69	--	--
करनाल	118	112	6	31.03.2010
पानीपत	46	43	3	15.04.2010
सोनीपत	73	67	6	31.03.2010
जीन्द	73	73	--	--
रोहतक	33	33	--	--
झज्जर	45	45	--	--
योग	691	676	15	--
द०ह०बि०वि०नि०				
फरीदाबाद	55	55	--	--
गुड़गांव	66	37	29	30.4.2010
नारनौल	128	128	--	--
भिवानी	72	60	12	31.03.2010
हिंसाार	131	122	9	31.03.2010
सिरसा	83	83	--	--
योग	535	485	50	--

Shifting of Indian Oil Depot

* 4. Shri Anil Vij : Will the Food & Supplies Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Indian Oil depots out of the town which are situated on G.T. Road, Ambala Cantt. in thickly populated locality; and
- if so, the time by which aforesaid depots are likely to be shifted ?

बिजली मंत्री (श्री नहेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) हाँ श्रीमान जी

(ख) समय अथवा बिता पाना सम्भव नहीं है।

Level of New Urlana Minor

* 21. Shri Krishan Lal Panwar : Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

- (a) whether it is a fact that water does not reach upto village Kurana situated on the tail of new Urlana Minor, District Panipat emanating from the Bitana canal; and
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to level the new Urlana minor; if so, the time by which the said minor is likely to be levelled ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) नहीं श्रीमान जी, जब बुटाना ब्रांच नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तब जिला पानीपल के गांव कुराना में जोकि नई उरलाना माइनर के अन्तिम छोर पर स्थित है, तक पानी नहीं पहुंचता है।
- (ख) नहीं श्रीमान जी।

Illegal Buses and Vehicles

* 50. Smt. Kiran Choudhary : Will the Transport Minister be pleased to state:—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to check plying of illegal buses and vehicles in the state; and
- (b) if so, the action taken against the defaulters ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) :

- (क) मोटर यान अधिनियम, 1988 और नियम के अन्तर्गत अवेस बसों और वाहनों के संचालन निरीक्षण / संचालन की शंकाओं के लिए राज्य सरकार ने पहले ही कार्य आरम्भ किया हुआ है। इसके लिए किसी तरह के अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2009-10 (अप्रैल 2009 से जनवरी 2010) के दौरान विभिन्न प्रकार के 29164 वाहनों का चालान किया और इन वाहनों से सम्झौता / जुर्माना में 33.90 करोड़ रुपये वसूल किए।

Land transferred by HSIIDC to Reliance

* 84. Sh. Ajay Singh Chautala, }
Sh. Krishan Pal Gurjar, } : Will the Industries Minister be pleased
to state:—

- (a) how much land has been transferred by HSIIDC to Reliance Haryana SEZ and how much land has been purchased by Reliance for setting up the said SEZ/SEZs in Haryana;
- (b) at what cost did the HSIIDC transfer the acquired land to Reliance for setting up the SEZ and at what price did Reliance buy the land for the said purpose directly from the farmers; and
- (c) how much employment was required to be generated in the sanctioned SEZs and how much employment has actually been provided particularly for those belonging to Haryana ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्री मान जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है।

- (क) मै० रिलायन्स हरियाणा विशेष आर्थिक जोन, को हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एच०एस०आई०आई०डी०सी०) द्वारा 1363.68 एकड़ भूमि स्थानांतरित की गई है। मै० रिलायन्स हरियाणा विशेष आर्थिक जोन ने भी 8202 एकड़ भूमि, भूमि मालिकों / किसानों से सीधी खरीदी है। जिसमें से 1201 एकड़ भूमि जिला गुड़गाँव तथा 7001 एकड़ भूमि झज्जर जिला में है।
- (ख) हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम ने अधिग्रहित भूमि रिलायंस हरियाणा एस०आई०डी० लिमिटेड को विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए 28.90 लाख रु० प्रति एकड़ की दर से स्थानांतरित की है। यकमूरत राशि के अतिरिक्त हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एच०एस०आई०आई०डी०सी०) को इस परियोजना में 10 प्रतिशत मैत्री इक्विटी मिलेगी। भू-मालिकों को तीस हजार रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से सुविधा (Annuity) दी जाएगी और अंत तक 8.38 करोड़ रु० भू-मालिकों को अदा किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त रिलायंस हरियाणा विशेष आर्थिक जोन ने भी, भू मालिकों / किसानों से सीधे तौर पर 22.00 लाख रु० प्रति एकड़ की दर से भूमि खरीदी है।
- (ग) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जब विशेष आर्थिक जोन पूर्णतः कार्यान्वित होगा, उसमें लगभग 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा (2 लाख प्रत्यक्ष तथा 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार)। इस परियोजना को चरणों में विकसित किया जाएगा। कम्पनी ने अभी परियोजना की प्लानिंग तथा अनुमोदन हेतु 460 व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ है, इनमें से 316 व्यक्ति हरियाणा से सम्बन्ध रखते हैं।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

11.00 बजे **Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under rule 30.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

“That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th March, 2010.”

Mr. Speaker : Motion moved -

“That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th March, 2010.”

Mr. Speaker : Question is -

“That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th March, 2010.”

The motion was carried.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना / वाक आऊट

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक इम्पोर्टेंट नॉन ओफिशियल रैजोल्यूशन दिया है कि लखवार, किसान और रेगुलर डैम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की हाउस की तरफ से रिकमंडेशन भेजी जानी चाहिए क्योंकि प्रदेश में पानी की शोर्टेज है। अध्यक्ष महोदय, ये न तो एस०वाइ०एल० कैनाल के केस को सुप्रीम कोर्ट में फालो अप कर रहे हैं और न ये प्रैजिडेंट रैफ्रेंस के लिए कमी कोर्ट में गए। (शोर एवं व्यवधान) हांसी बुटाना ब्रांच नई नहर इन्होंने बिना मंजूरी के ही बना दी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Majra Sahab, please listen. Please take your seat.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को और हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल सभी मेम्बरज बोल देंगे इसलिए नॉन ओफिशियल डे को नॉन ओफिशियल डे ही रखें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Majra Sahab, Please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात कहना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ मौजूद हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं और रामपाल माजरा जी भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। ये आज नॉन ओफिशियल डे की दुहाई दे रहे हैं जबकि इन्होंने

अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नॉन ओफिशियल डे नहीं करवाया। इस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है। (शोर एवं व्यवधान) हम तो हमेशा नॉन ओफिशियल डे करवाते रहे हैं। इस सरकार के पिछले 5 सालों में हम लगातार नॉन ओफिशियल डे करवाते रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने कभी कोई रैजोल्यूशन दिया ही नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस बार कोई रैजोल्यूशन नहीं था इसलिए हमने नॉन ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट कर दिया है। ओम प्रकाश चौटाला जी बी०ए०सी० के मੈम्बर हैं और उनकी सहमति से ही नॉन ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट किया गया था। ये लोग इस बारे में अपने नेता से बात कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, -----(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Majra Sahab, would you please sit down? (Interruptions)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, आज बजट पेश होना है। हरियाणा प्रदेश का बजट सेशन चल रहा है। बजट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। सारे प्रदेश की जनता की निगाहें बजट पर होती हैं कि हरियाणा सरकार अपना क्या बजट पेश करेगी ? बजट पर किसान की भी नजर होती है और व्यापारी की भी नजर होती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : वित्त मंत्री जी ने अभी बजट पेश किया ही नहीं इससे पहले ये बीच में कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार चुनकर आए हैं, इनकी कोई क्लास लभार ! (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, बजट पर कर्मचारियों की नजर होती है। सब अपना नफा नुकसान देखते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is not relevant. (Interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, how he can intervene like this. (Interruptions) The Finance Minister is waiting for presenting the Budget and in between he is making running commentary. He should not be permitted to behave like this. (Interruptions)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बजट तो पहले ही लीक हो गया। (शोर एवं व्यवधान) बजट की गोपनीयता तो रही ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए एज ए प्रोटेस्ट हम सदन से बाक आऊट कर रहे हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोक दल और शिरोमणि अकाली दल के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारे वर्कर्स पर 28 फरवरी, 2010 को चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के बारे में मैंने कॉलिंग अटेंशन भोशन दिया था। उसका क्या फेट है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आज वित्त मंत्री जी बजट रखेंगे और बजट के दिन प्रश्नकाल के अलावा और डिजनेस नहीं होता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए एज ए प्रोटेस्ट हम भी सदन से बाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2010-2011.

वित्तमंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना बजट पेश करूँ मैं लहे दिल से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यह बजट मैंने आपकी अपेक्षाओं और हरियाणा के हितों को सर्वोपरि रख कर तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। जैसे किशोरी शायर ने कहा है कि-

ओ तूने आज सोचा है,
वही मैंने भी सोचा है,
तेरी आंखों का एक रखाब,
इन आंखों से मैंने देखा है।

Hon'ble Speaker Sir,

I rise with a sense of pride and humility to present the Budget Estimates for the financial year 2010-11 before this august House. I stand with a sense of pride because our Government in its previous tenure performed exceptionally well on all fronts of development. The people of Haryana have appreciated this performance and, in a historic verdict, have returned our Government to power for another tenure. I stand in all humility in view of the tremendous faith our citizens have reposed in our Government. Sir, through this august House, I wish to assure the people of Haryana that this Government will totally dedicate itself to working for their welfare.

2. The world witnessed a severe economic recession in the previous year, which bordered on the worst economic depression the world has seen in recent past. Many financial and corporate bodies were driven to the brink of bankruptcy and millions of people were rendered jobless and homeless. Major economies were seriously threatened. Our country, in fact, is amongst the few nations less affected by the economic slow down. The credit for this goes to the robustness and self dependence



of the Indian Economy, as well as the strategic reforms and corrective measures taken in the recent past by the Government of India, under the competent leadership of Dr. Manmohan Singh. There is no doubt, Hon'ble Speaker Sir, that the world will take a long time to recover fully from this crisis. However, clear signs have now appeared that for our National and State economies, the worst may be over and the proverbial light is visible at the end of the tunnel. I am optimistic that the concerted efforts of our Government, with the support of the private sector and the people of Haryana, will be able to bring Haryana back on the path of growth and prosperity.

3. Sir, in times of severe economic recession, Government spending is one of the major tools for arresting downturn. In the wake of the recession, the revenue receipts of the State were adversely affected. There was a significant decline in the growth rate of State tax revenues and collections under Stamp & Registration and Urban Development. Moreover, for the welfare of its employees, the State has fully implemented the pay revision package, which has cast a burden of over Rs.4000 crore during the current year. Despite these strains, the Government has not shied away from its responsibilities, and has actually increased the outlay for Annual Plan 2009-10 from the budgeted figure of Rs. 10,000 crore to Rs. 10,400 crore in the Revised Estimates, which is 46.31% higher than the actual plan expenditure in 2008-09. This reflects the deep commitment of our Government to fight the economic recession with all measures at its disposal and to maintain the pace of development in the State.

4. Our National and State economies are now showing signs of resurgence from the depression. Our country is poised to achieve a growth of over 7% in its G.D.P. in the current year. In fact, the performance of the UPA Government at the Centre, under the visionary guidance of Chairperson Smt. Sonia Gandhi, is so remarkable that in the World Economic Forum, recently held in Switzerland, experts projected that India is likely to emerge as the fastest growing economy in the world in 4 to 5 years. The State tax revenue receipts are also improving and the VAT collections during the latter half of this financial year reflect very positive trends. Therefore, Speaker Sir, I am optimistic that Haryana is now emerging from the clutches of economic recession and our Government shall strive hard to take it further on the path of growth.

STATE ECONOMY

5. During the financial year 2008-09, the State economy witnessed a very healthy growth of 18.4% in the **Gross State Domestic Product (GSDP)** over the previous year at current prices. At constant prices, with base year 1999-2000, the growth in GSDP in 2008-09 is 7.9%. The Primary sector contribution to GSDP stands at 19.8% in 2008-09, whereas that from the Secondary and Tertiary Sectors stands respectively at 28.8% and 51.4%. The sectoral analysis reveals that, at constant (1999-2000) prices, the contribution of the Primary Sector to Gross State Domestic Product has registered an increase of 3.5 percent, while that of the Secondary Sector increased by 5.4 percent, and that of the Tertiary Sector recorded a growth of 11.2 percent. The declining share of the Primary Sector in GSDP, and the increasing share

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

of the Secondary as well as Tertiary Sector indicate a maturing of our economy, and its growth in the right direction. As per advance estimates, the GSDP at current prices for 2009-10 is likely to grow by 14.7%, while at constant (1999-2000) prices, the expected growth is 8.1%.

6. The per capita income of Haryana at current prices increased by 16.8% from Rs.59,008 in 2007-08, to Rs.68,914 in 2008-09. At constant prices, it increased by 6.2% from Rs. 39,462 in 2007-08 to Rs.41,896 in 2008-09. During the current year, it is likely to grow further by 13% to Rs.77,878 at current prices, and by 6.2% to Rs.44,493 at constant prices. Haryana has the second highest per capita income amongst the States in India, being second only to Goa.

7. It is a matter of great pride for all Haryanavis that Haryana has the highest per capita income among the major States in the country. However, our State has suffered a disadvantage on this account in the report of the Thirteenth Finance Commission (TFC). The TFC has used the per capita income of Haryana as the yardstick to measure a criteria called "Fiscal Capacity Distance", in its formula for horizontal distribution of central taxes amongst States. This criteria has been assigned the maximum weight of 47.5%, while the other criteria namely, **population, area and fiscal discipline** have been assigned weights of 25%, 10% and 17.5% respectively. Thus, due to this unique position, the share of Haryana in shareable pool of Central taxes has marginally come down from 1.075% to 1.048%. However, the total devolutions to Haryana under the 13th Finance Commission's recommendations are Rs.19,470.30 crore as compared to devolutions of Rs.8,040.44 crore during the 12th Finance Commission period. I congratulate the Union Government on increasing the size of the divisible pool of the Central taxes from 30.5% to 32%.

NEW INITIATIVES

8. It is estimated that, in order to sustain a growth of 8 to 9 percent in the national economy, an investment of nearly Rs.23 lakh crore is required on improvement of infrastructure during the 11th Five Year Plan. Investments of a similar order of magnitude would naturally be required in the State. You would agree, Sir, that this magnitude of investment is not feasible from the budgetary sources of the Government alone. Our Government is, therefore, keen on involving the Voluntary, Non Government and Private sectors in our development process. We believe the participatory mode of development to be the best for our State and our society, and this is reflected sharply in our new initiatives which I will now outline before this august Assembly.

Policy for Non Government Organizations and Voluntary Sector

9. Our Government recognizes that the Voluntary and NGO sectors can work as effective instruments of inclusive development, by helping with proper identification of beneficiaries, reduction of delivery costs, flexibility and simplicity of approach and greater community participation in formulation of new schemes. As a logical extension of Decentralized Planning, we propose to formulate a policy for engaging the Voluntary and NGO sectors as development partners for the State. The

policy would provide a framework for assisting such organizations through three instruments of partnership, namely, **Consultation** - through a formal process at the District and State level; **Strategic Collaboration** - to tackle complex interventions; and **Project Funding**. The project administration would be on the decentralized pattern recommended by the Planning Commission in the National Policy on the Voluntary Sector, and Mother NGO's will be involved to select, train, fund and concurrently monitor field projects being implemented by field NGO's on behalf of the Administrative Departments. This would bring in greater responsibility, transparency and accountability to our social sector projects.

Policy for Public Private Partnership Projects

10. In the complex current economic scenario, adequate development of social and physical infrastructure, which are pre-requisites for sustainable economic growth, can only come from pooling of all available resources - from government, non-government as well as private sectors. Therefore, the Public Private Partnership (PPP) mode of development assumes great significance. We propose to formulate a comprehensive policy on PPP projects in order to create an enabling environment in the State for facilitating private sector participation in improvement of the physical and social infrastructure. We intend to extend the PPP approach even to niche areas such as providing tertiary level health care at affordable cost to our population.

Haryana Infrastructure Development Board

11. Providing a framework for fast track implementation of the PPP projects is necessary to fully reap the benefits of the major investments we hope to initiate through the policy on PPP. We propose to do so by setting up **Haryana Infrastructure Development Board**, which would act as a nodal agency for conceptualization, financing, implementation, maintenance and operation of PPP projects in the State and also as a special purpose vehicle to take up major infrastructure projects funded out of State resources and other levies and charges.

East-West and North-South Expressway Corridors

12. Sir, our Government has the grand vision to spread the benefits of economic development to the remotest corners of Haryana. We propose to open up the hinterland by providing easy access by building an East West and a North South expressway corridor through the State. The project, likely to cost around Rs.2000 crore, will be in the PPP mode with a mixed model of BOT(Toll) and BOT(Annuity). The interior areas along the corridors will open up for industrial, commercial, estate development and allied activities, thereby creating enormous opportunities for growth and employment.

Haryana Metro

13. The proximity to Delhi is a unique advantage for Haryana, and our State territories constitute a large part of the National Capital Region. To fully exploit this advantage, we intend to set up Metro rail links connecting our bordering cities with Delhi. The 7.05 km long Gurgaon Delhi Metro link is near completion. We propose

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

to extend this to Manesar and also provide a high speed link to the Indira Gandhi International airport. Sikanderpur station is going to be connected via a 100% private Metro link to NH 8 by M/s Rapid Metro Rail, Gurgaon Ltd. Delhi metro is to be extended to Faridabad through a 13.87 km link. The project for linking Bahadurgarh to the Mundka border of Delhi is under process. At present, the various metro projects of Haryana are being implemented by the Delhi Metro Rail Corporation, which is a joint venture company of the Government of Delhi and the Government of India. For speedy and efficient implementation of our Metro projects, we propose to set up a joint venture company with the Government of Haryana holding a majority equity share, as has been done by the States of Karnataka and Tamil Nadu.

Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana

14. The population of our cities has been steadily increasing, and there is a growing need for holistic development of the urban areas with focus on improvement in infrastructure, efficient service delivery mechanisms, community participation and transparency. The Government proposes to launch **Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana (RGUDMH)**, a state-wide urban infrastructure development program, in all cities of the State excluding those covered under **Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission**. RGUDMH will be funded from the budgetary allocations as well as contributions from the Fund for Development of Major Infrastructure Projects, and will catalyze further investments under PPP mode. I propose to earmark Rs. 2500 crore for RGUDMH over the next five years, beginning with a sum of Rs.500 crore during 2010-11. RGUDMH will focus on the following components: affordable housing for the urban poor, including social and rental housing; in situ slum development in conjunction with the **Rajiv Awas Yojna** of the Government of India; Water Supply, Storm Water Drainage and Sewerage; integrated Solid Waste Management; and other civic amenities. For 2010-11, RGUDMH will broadly spend Rs.200 crore on projects for water supply and sanitation, Rs.100 crore on affordable housing projects, and the remaining funds will be used for special purpose infrastructure development projects in small and medium towns. The nodal agency for implementation of Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana shall be Haryana Urban Infrastructure Development Board which would now be headed by the Hon'ble Chief Minister. There will be a State Level Committee headed by the Chief Secretary for identifying and recommending the projects and overseeing their execution.

Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme

15. Our Government firmly believes that every human being has the right to a dignified old age and has significantly enhanced the old age pension. However, a large section of our working rural and urban population, particularly those working in the informal or unorganized sectors, is vulnerable to old age poverty. We propose to initiate **Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme** for the members of milk cooperatives and cane growers' cooperatives, wherein each member will contribute Rs.200 per month, the Society/Federation/State Government will co-

contribute Rs.100 per month, and the Government of India will co-contribute Rs. 1000 per annum. The contributions will go to a fund managed professionally as per the guidelines of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. The fund will provide the worker with a retirement pension to support him in his old age.

Economic Stimulus Package

16. Hon'ble Members would recall that my predecessor had introduced an Economic Stimulus Package in the last budget to help fight the recessionary trends of the economy. Various works have been initiated under this package, such as up-gradation of district hospitals, setting up of new medical colleges, improvement of water supply and sanitation facilities in urban areas, setting up of special care institutions for the disadvantaged sections of the society, restoration of water courses, housing for the industrial workers and construction of office and residential buildings for the new districts of Mewat and Palwal. Rs.332.56 crore have been released under the stimulus package so far, and I have made an allocation of Rs.713.79 crore for the works under the Stimulus Package for 2010-11.

17. Sir, before I take up sector-wise allocations, let me just highlight a few facts which will put the efforts of our Government in the right perspective. The total plan expenditure during the five years from 2000 to 2005 was only Rs.9,235.41 crore, whereas the plan expenditure for just the current year is going to cross Rs.10,400 crore! In the last five years, our Government spending on the State Plan was 230.13% higher than that of the previous regime. The average annual plan outlay growth rate during 2005-2010 is 37.83% per year, compared to just 4.8% during 2000-2005! This has been made possible by the strong commitment of our Government to development of the State.

POWER

18. Universal availability of quality power is critical for the economic development of the State, as well as for the comfort of its citizens. Our Government has accorded the highest priority to this sector and we are committed not only to adding adequate generation capacity to achieve the target of making Haryana a power surplus State, but also to upgrading our transmission and distribution systems for maximum efficiency and reliability. Due to the efforts of our Government, Hon'ble Speaker Sir, the average power availability per day in the State, which was only 578 lakh units in 2004-05, has gone up to 907 lakh units in the current year!

19. Tremendous progress is being made in enhancing the power generation capacity of the State. I would like to inform the Hon'ble Members that, in the period from 1999 to 2005, only 704.4 MW was added to the own generation capacity of Haryana, whereas, during the first tenure of our Government from 2005 to 2010, we have already added 1117.8 MW. The first 600 MW Unit of the 1200 MW **Rajiv Gandhi Thermal Power Project** at Khedar, Hisar has already been synchronized on 29.12.2009 and the second Unit will be ready for commissioning in April, 2010. This will be followed by the first 500 MW Unit of **Indira Gandhi Super Thermal Power Station** at Jhajjar, in July, 2010 and subsequently the second & third 500 MW Units

[किप्टन अजय सिंह यादव]

in December, 2010 and February, 2011 respectively. The first 660 MW Unit of **Mahatma Gandhi Super Thermal Power Project** at Jhajjar is targeted to be commissioned during December, 2011 and another 660 MW Unit-II will start generating power by May, 2012. For the 2800 MW **Nuclear Power Plant** to be set up at village Gorakhpur in district Fatehabad, pre-project work has been started by the Nuclear Power Corporation of India Limited for setting up two Units of 700 MW each in the first phase. Sir, you would agree that we are well on our way to double the availability of power in the State by 2011-12.

20. For up-gradation of the transmission network in the State, Rs.3,365.8 crore are being spent to add 25 substations of 66KV and above in 2009-10, and 72 substations in 2010-11. The first 400KV substation of the State has been set up at Kirori. We plan to augment our transformation capacity by 5000MVA during the 11th Plan.

21. Our effort, Sir, is to provide quality power to all citizens. Segregation of the rural domestic and agricultural loads and introduction of High Voltage Distribution System are important steps to improve the quality and efficiency of power supply in the rural areas. Under the **Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna**, 91,347 connections have so far been released to families below poverty line (BPL) this year.

22. I am allocating Rs.4,642.71 crore for this sector during 2010-11 which is 20.06% higher than the allocation for the current year. This includes Rs. 1,670.67 crore on Plan side and Rs.2,972.04 crore on Non-Plan side.

WATER SUPPLY AND SANITATION

23. Sir, a milestone was achieved in 1992, when drinking water supply facilities were extended to all the villages in the State. However, the approved norm of 40 liters per capita per day (lpcd) could not be achieved in some villages. A comprehensive survey in December, 2004 identified 1971 such villages. Our Government has accorded high priority to augmentation of water supply in these deficient villages, and I am proud to state that water supply in all 1971 deficient villages would stand augmented as per the approved norm by 31st March, 2010. In addition, augmentation of the water supply is being carried out in 950 villages under various schemes during this year.

24. The **Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Augmentation Project** in Mewat will be completed by March 31, 2010, covering 503 villages at a cost of Rs. 205.91 crore. Further augmentation of water supply from 55 lpcd to 70 lpcd in all these villages, with an outlay of Rs.94.58 crore, will commence in 2010-11. Under the **Indira Gandhi Drinking Water Scheme**, private water connections have been provided to 7.83 lakh Scheduled Caste households.

25. Adequate attention is also being given to improving the water supply and sanitation facilities in the urban areas. Our Government has waived the sewer connection charges for a period of one year from November, 2009 in order to encourage

the improvement of sanitary conditions in towns. Second water works based on canal water filtration have been commissioned in Rohtak and Dadri, and sewage treatment plants have been commissioned in Kaithal and Jind, while those in Rohtak, Hodal and Narwana are near completion.

26. In the National Capital Region, water supply projects for 10 towns and sewage system projects for 8 towns are under implementation with support from the NCR Planning Board. This year, sewage system projects in Sonapat and Gohana, and a water supply project in Sonapat have been approved.

27. Under the Economic Stimulus Package, 15 towns have been selected, namely, Ambala City, Bhiwani, Charkhi Dadri, Fatehabad, Hansi, Jullana, Kalayat, Assandh, Kaithal, Mahendergarh, Narnaul, Sirsa, Ellenabad, Tohana and Uchana for 100% coverage of Water Supply and Sewerage facilities. Phase-I of the project, amounting to Rs. 955.71 crore, has recently been approved by the Government.

28. I am allocating Rs.1,297.69 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 669.48 crore on Plan side and Rs.628.21 crore on Non-Plan side.

ROAD NETWORK AND PUBLIC WORKS

29. Sir, our Government is committed to improving the road network in the State. Up to 31.1.2010 during the current financial year, 3,903 Km. length of roads has been improved at a cost of Rs.1,476 crore under various schemes and projects. A length of approximately 4,100 kms will be widened/strengthened/reconstructed and improved in 2010-11. Under the **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna**, which is now a part of **Bharat Nirman Scheme**, 710 Kms. of rural road have already been improved during the current year at a cost of Rs. 239 crore. The PPP project for improvement of the Gurgaon-Faridabad and Ballabhgarh-Sohna road has already been taken up on BOT (Toll) basis with a negative grant of Rs.150.30 crore. The NCR Planning Board has sanctioned road projects worth Rs.638 crore this year.

30. Steady progress has also been made in the construction of Road Over-bridges. 55 ROB's have been sanctioned by the Government, 16 ROB's have been opened to traffic, and 13 more are under construction. To provide further impetus to road infrastructure development, the 2nd phase of the **Rajiv Gandhi Bridges & Road Infrastructure Program** has been taken up with an increased outlay of Rs. 5000 crore. Work is going on for completion of 75 km length of **Rohtak-Jhajjar-Rewari Railway line** and 88 km long **Sonapat-Jind Railway line**. These works, costing Rs. 596 crore, are under execution on 50:50 sharing basis with Indian Railways.

31. During this year, 114 public buildings have been completed at an approximate cost of Rs.215 crore. Work is going on in 700 building works having an approximate cost of Rs.1500 crore. Special attention is being given to maintenance and upkeep of public assets.

32. I am allocating Rs.1,938.95 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.1,311.97 crore on Plan side and Rs. 626.98 crore on Non-Plan side.

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

IRRIGATION

33. Speaker Sir, the Department of Irrigation will be completing a number of important projects during the coming financial year. The 70 km long **NCR Water Supply Channel** for carrying drinking water supply to Gurgaon, Manesar, Bahadurgarh, Sampla and Badli will be completed by June, 2010 at a cost of Rs.322 crore. **Kaushalya Dam** on the Ghaggar River in Panchkula district will be completed at a cost of Rs. 180 crore. **Carrier Lined Channel** for the supply of drinking water to Delhi, and the second phase of **Shahabad-Dadupur-Nalvi Project** will also be completed in the ensuing year. The capacity of **Western Jamuna Canal Main Line Lower** has been increased from 13,500 cusecs to 19,557 cusecs. Recharge channel for **Massani Barrage**, deepening of **Ottu Lake** and **Bhindawas Lake** are the other projects under implementation. To alleviate the problem of water scarcity in the backward area of Mewat, a detailed project report is under preparation for construction of the **Mewat Canal**.

34. Water is an important resource, and we are a water deficit State. The present irrigation water requirement of the State is around 36 million acre feet (MAF), whereas the surface and ground-water availability is merely 14 MAF. The deficient monsoons in the current year and lower levels in the Bhakra Dam and Pong Dam reservoirs did aggravate the problem of low water availability for our State. Our focus, therefore, has to be on saving water losses by all means, and ensuring optimal and equitable deployment of available water resources. During the next year, we propose to undertake construction of 500 new lined water courses and rehabilitation and remodeling of more than 500 minors and distributaries in the State, many of which were constructed more than 20 years ago.

35. I am allocating Rs.1,616.49 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.768.17 crore on Plan side and Rs.848.32 crore on Non-Plan side.

INDUSTRIES AND COMMERCE

36. Haryana has emerged as a favoured investment destination in northern India for industry, and scores amongst the top States in India on per capita investment performance. Provision of quality infrastructure following the Industrial Model Township (IMT) approach has been a key factor in this performance. Our future plans include expansion of IMT, Manesar, development of an IMT near Roz-ka-Meo and an IMT near Kharkhauda. The projects for development of an IMT at Faridabad, Phase-II of IMT Rohtak, Phase-IV of Growth Centre Bawal, Manakpur, Barhi and Panipat are under process. Establishment of an IMT in district Ambala is also under consideration. The HSIIDC proposes to invest over Rs. 1,200 crore on land acquisition and development of industrial infrastructure during the ensuing year.

37. **Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project(DMIC)** is being developed along the alignment of the Delhi-Mumbai freight corridor. A Multimodal Logistic Hub, an Exhibition-cum-convention Centre and a Mass Rapid Transport system from Gurgaon to Bawal have been identified as the early bird projects under this mega

project. Under the Economic stimulus Package, special dispensation is being made for creation of housing stock for industrial workers.

38. To equip our own people to reap the advantage of industrialization, our Government is establishing a number of skill development facilities. These include the **National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM)** at Kundli, **Footwear Development and Design Institute** at IMT Rohtak, **Central Institute for Plastic Engineering and Technology (CIPET)** at Murthal, and **Indian Institute of Corporate Affairs** at IMT Manesar. I am confident that the various steps taken by the Government for development of infrastructure, improved power availability and congenial labour relations, along with a new Industrial Policy, would take the State to new investment horizons.

39. I am allocating Rs.164.06 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 125.61 crore on Plan side and Rs.38.45 crore on Non-Plan side.

INFORMATION TECHNOLOGY AND e-GOVERNANCE

40. Alongside the overall industrial investment, Haryana has emerged as a preferred investment destination for the IT Industry as well. Out of a total of 46 SEZ's that have been formally approved for the State of Haryana, 35 are in the IT Sector. In addition, the State has granted licences to 27 proposals for the establishment of IT/Cyber Parks. Software exports from Haryana have exceeded Rs.21,000 crore during 2008-09.

41. Our State is among the leaders in the establishment of Information Technology infrastructure under the National e-Governance Plan. The **State Wide Area Network** has already been set up. The **State Data Centre** is going to be established in the ensuing year. We are taking concrete steps to leverage the use of information and communication technology in governance. Major e-Governance projects are under implementation in the Food and Supplies Department, Transport Department, Commercial Taxes Department and Treasuries. We propose to create a cadre of IT professionals in the State for smooth implementation and sustenance of e-Governance initiatives in the State.

42. I am allocating Rs.19.59 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 19.35 crore on Plan side and Rs.0.24 crore on Non-Plan side. There will be substantial additional investment by the line departments on their individual e-Governance initiatives.

TRANSPORT

43. The vision of our Government is to make Haryana a model State with fast, equitable and inclusive development. Therefore, we lay as much emphasis on improving citizen services across the State as we do on creation and up-gradation of infrastructure for economic growth. In order to provide reliable, safe and efficient passenger transport services to each and every village in the State, a **comprehensive passenger transport policy** is being formulated. The policy aims at setting up a state-wide network of bus services, comprising both private service operators and

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

Haryana Roadways. To promote road safety in the State, **Institutes of Driving Training and Traffic Research** are being established in collaboration with auto majors such as Maruti Suzuki, Ashok Leyland and Tata Motors at Rohtak, Kaithal and Bahadurgarh.

44. To meet the needs of our citizens, our Government intends to increase the total fleet strength of Haryana Roadways to 4500 buses by the end of the 11th Plan period. Special attention is being paid to inter-city transportation and a **City Bus Service** is proposed to be setup under PPP mode in Gurgaon. The Faridabad-Gurgaon-Delhi bus service has recently been started under JNNURM. We also propose to construct Multi-modal Hubs/ Modern Bus Stands under PPP mode at 20 locations in the State.

45. I am allocating Rs.1,142.10 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.92.72 crore on Plan side and Rs.1,049.38 crore on Non-Plan side.

AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS

46. Sir, this sector continues to be the mainstay of livelihood for a majority of our population. The great progress made by our State in this sector is reflected in our food grain production, which has increased six fold from 25.92 lakh tons at the inception of Haryana in 1966-67, to a record 161.66 lakh tons during 2008-09. The weak monsoons this year have led to a marginal reduction in the cultivated area under both Kharif and Rabi crops. However, due to the efforts of our farmers and the Government, there is no reduction in production and we are likely to achieve the target of production of 167.14 lakh tons during the current year.

47. The consumption of fertilizer has touched 14.35 lakh MT and is 11.24% higher than last year's consumption. However, declining soil health is a matter of concern for us, and micronutrients play an important role in soil fertility. Hence, the Agriculture Department has prepared a new plan scheme for managing micronutrient deficiency, in which 50% subsidy will be provided for micronutrient fertilizer up to a maximum of Rs. 500/- per hectare with a ceiling of 2 hectares per farmer. Various other schemes for restoring soil health and increasing agricultural production will continue in the ensuing year.

48. Keeping in view the interest of the farmers, the State Government has fixed the basic cane price of early, mid & late maturing varieties of sugarcane at Rs.185/-, Rs.180/- and Rs.175/- per quintal, respectively, during the current crushing season which is the highest State Administered Price in the country. In addition, our cooperative sugar mills have given a bonus of Rs.25 per quintal. The Shahabad, Karnal and Panipat sugar mills have further shared their profits with the farmers by giving an additional bonus of Rs.40, Rs.30 and Rs.20 per quintal respectively. To enhance sugarcane production in the State, a **Technology Mission on Sugarcane** is proposed by our Government for 2010-11. Moreover, the basic cane prices for early, mid and late varieties have been further enhanced respectively to Rs.210/-, 205/- and Rs.200/- per quintal for the crushing season of 2010-11. The bonus will be decided before the crushing season commences.

49. To protect our farmers from the vagaries of nature, a new insurance scheme called **Weather Based Crop Insurance Scheme** has been conceived to compensate yield loss due to adverse weather conditions. The scheme is being implemented on a pilot basis for wheat crop during Rabi season 2009-10 in Ambala II, Buhain and Tohana blocks.

50. Animal Husbandry and Dairying are an integral part of our agrarian economy, and the Government is fully conscious of its contribution to the prosperity of our farmers. A network of 2,789 Veterinary Institutions caters to the 90.93 lakh strong livestock population of the State. Efforts will be made to open 80 new Veterinary Institutions during 2010-11. One pet animal medical centre-cum-teaching hospital has been set up at Panchkula and super specialty poly clinics have been established at Sonapat and Bhiwani. Another such poly clinic is being setup at Sirsa. The Haryana Dairy Development Cooperative Federation is providing procurement, processing and marketing support to the 5100 dairy cooperatives in the State. Sir, you will be happy to know that farmers are being paid Rs.340 per kg fat for milk at present, whereas they were being paid a mere Rs. 165 per kg fat in 2005.

51. The cooperative movement has played a pivotal role in supporting the agriculture and allied sector in the State. Over 35 thousands Cooperative Societies of different types, having over 57 lakh members, are working in the State. The cooperative credit structure at the grass root level has been restructured by amalgamating 2,441 Primary Credit Cooperative Societies into 620 Primary Agricultural Cooperative Societies. Under the **Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme** of Government of India, loans worth Rs.830.78 Crore have been waived for 2,61,250 small and marginal farmers; while 2,00,734 other farmers have been provided a relief of Rs. 343.16 crore under the scheme.

52. In March 2009, our Government slashed the rate of interest on crop loans from 11% to 7%. The State Government is giving an interest relief of 2% on timely repayment of crop loans, while the Government of India is paying an interest relief of 1%. With these interest subventions, the effective rate of interest on crop loan is now just 4%. For long term non-agricultural loans, the State Government has increased interest subvention from 3% to 5% under the **Timely Repayment Incentive Scheme**, which has been extended up to 31-12-2010. Moreover, our Government has also modified the provision in the **Haryana Cooperative Societies Act, 1984** under which cooperative loans were recovered as arrears of land revenue. Henceforth, no farmer in the State can now be arrested for recovery of cooperative loans. This, Hon'ble Speaker Sir, shows how deeply our Government respects the dignity of our farmers.

53. The State Government has set up the **State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA)** in accordance with the guidelines of the Government of India. This Fund will be utilized for the protection and management of natural forests and wildlife sanctuaries, compensatory afforestation, environmental services and research and development. Under the Forest (Conservation) Act, 1980, a contribution of Rs.187.43 crore has already been made to this fund by the User agencies against sanctioned proposals.

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

54. I am allocating Rs.1,073.62 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.540.66 crore on Plan side and Rs.532.96 crore on Non-Plan side.

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATS

55. Our Government will continue its focus on the development of the rural areas. A number of schemes are being implemented, both in the Central and State sectors, for up-gradation of rural infrastructure, employment generation and alleviation of poverty as well as other pressing issues. Under the **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme**, a sum of Rs.78.49 crore has been utilized up to the end of January, 2010 for generating 39.68 lakh person-days of employment in the rural areas of the State. Assistance of Rs.18.40 crore has been provided to 11,851 swarozgaris under the **Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana**. To further promote self-employment, **Rural Development and Self-employment Training Institutes** are being set up in existing ITI campuses in five districts. Under the **Indira Awaas Yojana (IAY) Scheme**, 15,604 houses have been constructed and 6,309 houses are under construction in the current financial year. **Backward Regions Grant Fund** scheme is being implemented in Mahendergarh and Sirsa districts to bridge critical gaps in village infrastructure and facilities.

56. Our Government is providing free residential plots of 100 sq.yard each to eligible Scheduled Caste, Backward Class (A) and Below Poverty Line families in planned and developed lots under the **Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojna**. Out of 6 lakh identified eligible families, 2.91 lakh families have been allotted plots in the first phase in villages where panchayat land was available. The remaining villages will be covered in the second phase. Villages having more than 50% SC population are being provided basic infrastructure under the **Mukhya Mantri Anusuchit Jaati Nirmal Basti Yojna**. In the first phase, Rs.117.85 crore have been released for taking up 442 works in 391 villages. **Mukhya Mantri Sanitation Incentive Puraskar Yojna** has been launched to provide incentive to panchayats for improving cleanliness and eradicating the practice of open defecation in the villages.

57. I am allocating Rs.956.17 crore for this sector during 2010-11 which is 7.09 % higher than the allocation for the current year. This includes Rs.613.54 crore on Plan side and Rs.342.63 crore on Non-Plan side.

URBAN DEVELOPMENT

58. Sir, I have already mentioned the great importance that our Government gives to the improvement of infrastructure and facilities in urban areas. The financial position of many of the urban local bodies is weak, and the economic slowdown has further affected their finances. In order to provide a steady source of income to our local self government entities, I propose to impose a small surcharge on VAT in the State. Out of the collections under the surcharge, 80% will be given to Urban Local Bodies and 20% will be given to Village Panchayats. This will help these local bodies take up new development projects in their areas on a sustained basis.

59. City Development Plans (CDP) of 73 towns have been prepared to map their basic infrastructure gaps and needs. Under the **Jawaharlal Nehru Urban**

Renewal Mission (JNNURM) of the Government of India, Rs.823.33 crore have been sanctioned for 7 projects for Municipal Corporation, Faridabad. Now Panchkula has also been included under JNNURM and its CDP is under consideration of the Government of India. Under the **Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)**, new projects for Integrated Solid Waste Management at Rohtak, Karnal, Indri, Yamunanagar & Jagadari and projects for Sewerage System & Sewerage Treatment Plant at Bahadurgarh Phase-I and II, Ambala Sadar, Narnaul and Charkhi Dadri have been sanctioned for Rs.164.07 crore. Under the **Integrated Housing and Slum Development Program**, 16,608 dwelling units are being constructed for slum dwellers.

60. To ease the mounting pressure on infrastructure in the mega cities like Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad, the Government of India has launched a centrally sponsored scheme called **Urban Infrastructure Development in Satellite Towns**. The scheme aims at developing satellite towns near the mega cities as counter magnets by upgrading urban infrastructure facilities such as transport, drinking water, sewerage, drainage and solid waste management. The Government of India will bear 80% of the cost of the scheme, while the balance will be equally shared by the State and the urban local body. The scheme will be implemented in Sonapat town for which a provision of Rs.100 crore is proposed for 2010-11.

61. I am allocating Rs.1,447.14 crore for this sector during 2010-11 which is 26.50 % higher than the allocation for the current year. This includes Rs.1,324.83 crore on Plan side and Rs.122.31 crore on Non-Plan side.

SCHOOL AND HIGHER EDUCATION

62. Education is the cornerstone of development, and our insurance for the future of the State. Its critical importance and centrality to human resource development cannot be over-emphasized. Speaker Sir, this Government is committed to making education universally accessible and inclusive for all sections of the society. The Hon'ble Members would be happy to know that now, in Haryana, a primary school is available to a child within a radius of 1.03 km, a middle school within 1.07 km, a high school within 1.52 km and a senior secondary school within 2.28 km. This Government has upgraded 21 Middle Schools to High Schools and 53 High Schools to Senior Secondary Schools. Our seriousness in this sector can be gauged from the fact that the total budget of the education department, which was Rs.1,733.18 crore in 2004-05, has gone up to Rs.5,331.35 crore in Revised Estimates 2009-10.

63. We do realize that creation of infrastructure, though necessary, is by no means sufficient for quality education. A number of schemes are being run by the State and the Centre to attract children to schools and to retain them. These include the **Mid-day Meal Scheme**, the **Rajiv Gandhi Scholarship Scheme** and other scholarship schemes, **Monthly Incentive Schemes**, **Cash Awards Scheme** and others. The **Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)**, implemented in financial partnership with the Central Government, has been instrumental in improving the quality of elementary education by provision of teachers, opening of schools and alternate school facilities,

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

quality improvement programs and creation and improvement of infrastructure. Following the success of SSA, with the intention of making quality secondary education available, accessible and affordable to all young persons in the age groups 14-16 years, the Government of India has launched the **Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan**. The RMSA is funded by the Centre and State Governments in the ratio of 75:25, and provides for various improvement schemes on the pattern of Sarv Shiksha Abhiyan.

64. To improve female literacy, the **Saakshar Bharat Scheme** of the Government of India has been launched in Karnal district this year. The scheme will subsequently be extended to 9 more districts having 50% or less adult female literacy, namely, Kaithal, Jind, Fatehabad, Hisar, Sirsa, Bhiwani, Gurgaon, Mahendergarh and Faridabad.

65. Higher Education has a different set of challenges and issues from School Education and is critical to qualitative social growth of the State. To ensure closer attention and a sharper focus on its development, our Government has created a separate administrative department of Higher Education. For expansion of outreach, one Central University at Mahendergarh and two private universities have already become operational. More private universities are at advanced stages of being set up. BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonapat will be further improved and strengthened. A number of schemes are also being implemented to enable children from weaker sections of the society to acquire higher education.

66. Teaching activity in schools gets disrupted every month with the retirement of teachers. In order to avoid such disruption, our Government has taken a historic decision to re-employ retiring teachers till the end of the academic session.

67. I am allocating Rs.5,946.29 crore for this sector during 2010-11 which is 11.53 % higher than the allocation for the current year. This includes Rs.1,490.32 crore on Plan side and Rs.4,455.97 crore on Non-Plan side.

TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

*12.00 बजे 68. Quality technical and professional manpower is the most important resource for the socio-economic development of a State. At the time of its inception, Haryana had only 6 polytechnics and one engineering college in the State with a total annual intake of 1,341 students. Now, 1,12,910 students pass out every year from 546 institutions, including 141 engineering colleges.

69. The network of technical institutions is continuously growing. 6 new Government Polytechnics have become operational at Madalpur (Faridabad), Hathnikund Barrage (Yamunanagar), Mehram (Rohtak), Basai (Gurgaon), Indri (Mewat) and Mandkola (Mewat). Seven more polytechnics are being opened in Rewari, Kaithal, Panchkula, Panipat, Fatehabad, Kurukshetra and Yamunanagar districts. The prestigious **Indian Institute of Management (IIM)** is to be set up in 213 acres of land at village Gharnavati in Rohtak.

70. To prepare our students for skilled industrial jobs, a network of 109 Government Industrial Training Institutes and 74 private Industrial Training Centers is operating in the State with an annual intake of 27,792 and 10,976 students, respectively. 26 New ITI's will be opened in the next three years, while 22 existing ITI's will be expanded. Besides, 29 ITI's and 1,500 skill development centers will be established in PPP mode in the State during the next five years.

71. I am allocating Rs.431.12 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.300.11 crore on Plan side and Rs.131.01 crore on Non-Plan side.

HEALTH

72. One of the key functions of a democratic government is to provide reliable, affordable and accessible healthcare to its citizens. This Government is striving hard to improve the quality of health infrastructure, the availability and quality of doctors, availability of free medicines, and efficient delivery of health and medical services. The State is providing healthcare through 52 hospitals, 94 Community Health Centers, 441 Primary Health Centers, 2,465 Health Sub-centers, 20 District TB Hospitals and 51 Dispensaries. Free drug supply to all the patients and introducing the Surgery Package Program are among the major initiatives of the Health Department. Six district hospitals at Gurgaon, Hisar, Bhiwani, Faridabad, Sonapat and Rohtak, are being upgraded into state-of-the-art Multi Specialty Hospitals with an expenditure of more than Rs.102 crore under the Economic Stimulus Package. Three district hospitals at Rewari, Panipat and Panchkula will be upgraded and Civil Hospital at Dadri will be expanded to 100 beds during 2010-11.

73. Construction of two medical colleges at Khanpur Kalan (Sonapat) and Naihar (Meerut) has been started under the Economic Stimulus Package at an estimated cost of Rs. 617.61 crore. The Government has also announced setting up of Kalpna Chawla Medical College at Karnal. Pt. B.D. Sharma Post Graduate Institute of Medical Studies, Rohtak is to be upgraded to the level of All India Institute of Medical Studies under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna. For this purpose, a sum of Rs.125 crore has been earmarked by the Government of India and Rs.25 crore will be contributed by Haryana.

74. On 26 January, 2010, our Government launched the Nehru Bal Drishti Yojana, a new scheme under which eye collection centers have been set up and linked to "102" services in each district. At present one Eye Bank exists in the State at PGIMS, Rohtak. We propose to set up another Eye Bank in the State in the ensuing year.

75. I am allocating Rs.1,125.48 crore for this sector during 2010-11 which is 6.07 % higher than the allocation for the current year. This includes Rs.455.85 crore on Plan side and Rs.669.63 crore on Non-Plan side.

SOCIAL WELFARE

76. Haryana Government is fully committed to the welfare of the vulnerable sections of the society and has undertaken a series of effective steps to provide social

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

security to the aged, widows, destitute women, handicapped persons, eunuchs, dwarfs, persons from minority communities and families with only girl child/children. A provision of Rs.1,465.46 crore has been made for these schemes for the current year.

77. To ensure that citizens with disabilities are not left out of the mainstream of development, our Government has launched an ambitious **Jawahar Social Infrastructure Mission** to take up projects for this section of our society. Under JSIM, we propose to set up 10 schools for the visually challenged children, 8 schools for the children with hearing and speech impairments, 6 schools for the differently abled children, three State Level Institutes for providing vocational training to persons with different physical disabilities, 4 Senior Citizens' homes, 21 Vocational Training Centers and two Life Long Homes for the differently abled persons in the next three years at a cost of Rs.150 crore.

78. In order to encourage Scheduled Caste girl students to go for higher education, a new scheme namely **Anusuchit Jati Chhatra Uchch Shiksha Protsahan Yojana** has been launched for the year 2009-2010 wherein annual scholarships ranging from Rs.5000 to Rs.14000 are being provided to Scheduled Caste girl students studying science, commerce or professional courses. **Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana** has been extended to post graduate classes. The popular **Ladli** scheme for supporting the second girl child, initially launched for five years, has been extended for another five years.

79. I am allocating Rs.2,167.15 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 2,010.20 crore on Plan side and Rs.156.95 crore on Non-Plan side.

RECRUITMENT IN GOVERNMENT

80. In a democratic setup, the government is a vehicle for the delivery of development, infrastructure and social services to the citizens. Therefore, the efficiency of the government as an organization, as well as the bottlenecks in its operations, assumes importance. One of the main bottlenecks in government functioning at present is the delay and inconsistency in recruitment of human resource. We have, therefore, identified the services and cadres which need frequent recruitment to meet the requirements of different departments, public undertakings, boards and corporations, and decided that the Haryana Public Service Commission and the Haryana Staff Selection Commission will hold annual examinations, at pre-determined dates, for recruitment thereto, so that the candidates do not have to apply time and again. Accordingly, the HPSC will annually conduct the Engineering Services Combined Examination, Agriculture and Allied Services Combined Examination, and Legal and Allied Services Combined Examination, whereas the HSSC will conduct Graduate Level Combined Examination, Junior Engineers and Allied Services Combined Examination, Clerks Grade Examination, Drivers Combined Test and Steno-typists/Stenographers Combined Examination.

81. Basic minimum eligibility qualification in respect of similar category posts shall be uniform in all Departments, Boards, Corporations, Companies and Societies. There shall be a Uniform Application Form in computer readable format.

Self certified copies of certificates relating to caste, residency, age, physical handicap etc. will be accepted at the application stage. Original certificates shall be checked only at the time of interview and joining of selected candidates.

82. We have also decided that all fresh recruits will undergo mandatory induction training for 3 months after joining so that they are well prepared for their respective jobs. They will be given postings only after completing such induction training.

BUDGET ESTIMATES 2010-11

83. Sir, I would like to draw the attention of Hon'ble Members to the fact that the Budget Estimates I bring before this august House for voting this year are in a slightly modified form. You will notice, Sir, that this time we are proposing 45 Demands for Grants as against the traditional 25 Demands. Recognizing that the State expenditure pattern has undergone significant changes in the last few years, the clubbing of departments under various Demands has been rationalized. This has been done to streamline departmental spending, and to bring greater transparency, accountability and control in the Budget. It would also instill greater discipline in matters of re-appropriation and avoid large variations between the Budget provisions and actual expenditure. The Hon'ble Members will also get a clearer picture of the expenditure they are voting on.

84. I now proceed to present before this august House the Budget Estimates for the financial year 2010-11. The Financial Year 2009-10 opened with a deficit of Rs.602.41 crore as per RBI books and is likely to be closed with a deficit of Rs.634.06 crore representing a transaction deficit of Rs.31.65 crore during the year on annual account. Under the Budget Estimates 2010-11, the Total Receipts (net of Public Debt) are projected at Rs.30,085.98 crore, of which Revenue Receipts are Rs. 24,540.83 crore, while Capital Receipts (net of Public Debt) are Rs. 5,545.15 crore. These signify, respectively, an increase of Rs. 1,729.05 crore, Rs.1,538.93 crore and Rs.190.12 crore over the corresponding projections in the Revised Estimates 2009-10. The Total Expenditure (excluding Repayments) under the Budget Estimates 2010-11 is projected at Rs.33,600.84 crore, of which Revenue Expenditure is Rs. 28,482.64 crore, while the Capital Expenditure is Rs.5,118.20 crore. These signify, respectively, an increase of Rs. 2,004.73 crore, Rs. 1,818.49 crore and Rs.186.24 crore over the corresponding projections in the Revised Estimates 2009-10. The Budget Estimates 2010-11 project a Revenue Deficit of Rs.3,941.81 crore and a Fiscal Deficit of Rs.8,815.64 crore. The Balance form Current Revenues for 2010-11 is projected to be Rs.845.82 crore. The Revenue Deficit is primarily on account of the impact of the 6th Pay Commission, with the annual pay increase impact for 2010-11 amounting to about Rs.2600 crore, and the arrears of pay and pension amounting to about Rs.1570 crore.

85. Hon'ble members would be glad to note that our Government has made investments on capital expenditure to the tune of Rs.17,879 crore between 2005-2010, compared to the capital expenditure of only Rs.8,308 crore during 2000-2005.

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

This Government, Speaker Sir, is totally dedicated to creating a bright future for our State.

86. Let me now indicate the sectoral allocations in the Budget Estimates 2010-11. The Agriculture and Allied sector is slated to receive Rs.1,073.62 crore, the Power sector is slated to receive Rs.4,642.71 crore, the Transport sector is allocated Rs.1,142.10 crore, the Irrigation sector is projected to receive Rs.1,616.49 crore, the Water Supply and Sanitation sector is slated to receive Rs.1,297.69 crore, the Urban Development sector is allocated Rs.1,447.14 crore, the Education sector, including Industrial Training and Technical Education, is projected to receive Rs.6,377.41 crore, the Health sector is slated to receive Rs.1,125.48 crore, the Social Justice and Empowerment including Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes sector is allocated Rs.2,167.15 crore, and the Rural Development and Panchayat sector is slated to receive Rs.956.17 crore.

87. As against the Annual Plan projections in the Budget Estimates 2009-10 at Rs.10,000 crore, revised further to Rs.10,400 crore, the allocation for the Annual State Plan 2010-11 is proposed at Rs. 10,500 crore. In addition to it, an outlay of Rs.1,363.58 crore for the Centrally Sponsored Schemes and other development plan schemes has also been included on the Plan side, boosting the composite Plan outlay in the Budget Estimates 2010-11 to Rs. 11,863.58 crore.

88. Let me confess, Sir, that the decision to come before this august House with a revenue deficit budget this year was not an easy one. It would have been an easy escape route for me to prepare a budget without deficit by suppressing expenditure. But the collective conscience of this Government does not allow such populist measures at the expense of the future of our people. It was a conscious decision of our Government not to curtail investment expenditure on the ongoing projects and important projects in the pipeline, in the long term interest of this State, and we have targeted a modest increase in plan spending for our Annual Plan 2010-11 accordingly. We do propose to exercise economy and restraint in general expenditure in the government departments, and, indeed, our Government has already adopted significant economy measures, but the pace of development of Haryana has to be maintained at all costs.

89. Our effort in this Budget has been to consolidate the gains that have been made by the State in the last five years. The budget deficit is within manageable limits and the measures for further financial discipline are likely to reduce its pitch further. Our tax revenue has already started recovering its normal growth, and can be expected to exceed the modest targets kept in the Budget proposals. It is also expected that the share in central taxes and other devolutions would go up during the year, as the implementation of revised pay structure across the country and payments of arrears are sure to increase the income tax receipts of Central Government. I, therefore, feel confident in assuring the House that we will be able to implement all our projected programs very successfully while achieving the targets fixed in the Budget. For this,

I solicit the active cooperation and support of all the Hon'ble Members of this august House, and through them, of all the proud citizens of Haryana.

CONCLUSIONS AND COMMENDATION

90. Before I conclude, I would like to acknowledge the untiring efforts and dedication put in and exhibited by the Finance Secretary and his colleagues in the Finance Department and the National Informatics Centre and its employees who persevered day and night to help me prepare and present these Budget proposals.

91. Hon'ble Speaker Sir, through you I want to extend the most solemn assurance to this House and to the people of Haryana at large, that we would summon all resources available to us and dedicate ourselves to the task of taking Haryana forward on the path of development at the same pace and with the same zeal that we have shown in the last five years.

92. Sir, with these words now I commend the Budget Estimates 2010-2011 to this House for its consideration and approval.

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसे निर्णय भी लेने जरूरी होते हैं जो कि समस्त जनता के हितों को ध्यान में रख कर लेने होते हैं क्योंकि ऐसे निर्णय ही हमें नया अनुभव और नया आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। अंत में मैं कहूंगा :-

क्यों उन्हें हम जिन्दी में क्या होगा,

कुछ न होगा तो तड़की होगा।

Sir, with these words now I commend the Budget Estimates 2010-2011 to this House for its consideration and approval.

JAI HIND

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 10.00 A.M. on Thursday, the 11th March, 2010.

***12.24 hrs.** (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Thursday, the 11th March, 2010.)

